लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

गुरुवार, 27 अगस्त , 2026

वर्ष : 12 | अंक: 3

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

'एक देश, एक चुनाव': कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 'असंभव' बताकर दागा सवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बुधवार को 'एक देश, एक चुनाव' की व्यावहारिक व्यवहार्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत में एक साथ चुनाव कराने का विचार बिल्कुल भी व्यावहारिक और संभव नहीं है, खासकर तब जब किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसका बहुमत खत्म हो जाए। राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की चुनौतियों पर करते हुए, मसूद ने विधानसभाओं के कार्यकाल और उनके समय से पहले भंग होने की स्थिति को लेकर चिंता जताई। मसूद ने कहा कि यह कैसे संभव है? अगर किसी वजह से विधानसभा में बहुमत कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो अगला चुनाव उसी समय-सीमा के लिए होगा... यह इस देश में बिल्कुल भी व्यावहारिक और संभव नहीं है। विपक्ष की आशंकाओं का जवाब देते हुए, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने तर्क दिया कि एक साथ चुनाव लागू करने से चुनाव से जुड़े खर्च में काफी कमी आएगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। चंदोलिया ने ANI से कहा कि अगर देश में 'एक देश, एक चुनाव' लागू होता है, तो अलग-अलग चुनावों पर खर्च होने वाला बहुत सारा पैसा बचेगा और इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस बीच, पटना में बिहार के मंत्री राम कृपाल यादव ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि बार-बार होने वाले चुनाव खर्च से प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर ऐसा बोझ पड़ता है जिसे संभालना मुश्किल होता है। ANI से बात करते हुए यादव ने कहा कि यह सरकार अपने काम को गंभीरता से लेती है और सभी नियमों और कानूनों का पूरी तरह पालन करती है। इसीलिए 'एक देश, एक चुनाव' जरूरी है; लगातार होने वाले चुनावों से देश और सरकार पर भारी बोझ पड़ता है। इसे समझते हुए, प्रधानमंत्री ने 'एक देश, एक चुनाव' को सही और जरूरी माना है।

तिब्बत में फटे ग्लेशियर से नेपाल में तबाही: कई गांव और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहे, सात लोगों के मिले शव

काठमांडू, एजेंसी। उत्तरी नेपाल की भोटे कोशी नदी में बुधवार को अचानक बाढ़ आ गई। जिसमें सात लोगों की शव मिले है। जिससे तिब्बत सीमा के पास रसुवा जिले के कुछ हिस्से तबाह हो गए। घरों, गाड़ियों, पुलों और बुनियादी ढांचे के परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। इस स्थानीय मीडिया के अनुसार बाढ़ में हजारों लोग लापता है। जिसके बारे में कई जानकारी नहीं है। उतरी रसुवा में एक सीमा चौकी पर तैनात नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के चार जवान अचानक आई बाढ़ के कारण लापता हो गए हैं। इसके अलावा, स्थानीय मीडिया में के अनुसार, रसुवा सीमा शुल्क कार्यालय के 14 कर्मचारी भी संपर्क से बाहर हैं। नेपाल के स्वतंत्र बिजली उत्पादक संघ के अनुसार, बाढ़ से 15 हाइड्रो पावर परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। इनमें से 10 चालू है और पांच निर्माणाधीन है। नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की सूचना स्थानीय समयानुसार सुबह करीब नौ बजे मिली। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ का पानी तिब्बत की ओर से आया प्रतीत होता है।

योगी सरकार का बेटियों को तोहफा, 50 हजार छात्राओं को देगी स्कूटी, मुख्यमंत्री ने किया एलान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एलान किया है। योगी सरकार प्रदेश की 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देगी। बुधवार को लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा' योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम ने ये एलान किया है।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी की डबल इंजन सरकार की हर एक योजना बेटियों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। 2017 के पहले प्रदेश की क्या स्थिति थी। पहले कहा जाता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। प्रदेश में

बेटियों का सम्मान, शिक्षा और भविष्य सुरक्षित नहीं था। प्रदेश में उत्सव के पहले दंगे हो जाते थे।

हर तरफ अव्यवस्था और अराजकता का माहौल था। हम उस दौर को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं पर जब मोदी जी के नेतृत्व में यूपी में डबल इंजन की सरकार आई तो अराजकता को उत्सव बना दिया गया है। सरकार की हर योजना का केंद्र बेटी है। पहले तो हर योजना में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी होती थी। अब बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जेल या जहन्नुम में कोई एक जगह मिलेगी। पहले बेटियों की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर थी पर अब सिस्टम और तकनीक पर आधारित है।

'निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा' योजना का शुभारंभ कर दिया। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना का लाभ रोजाना करीब 88438 महिला यात्रियों को मिलने का अनुमान है। योजना के तहत निशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की ओर से विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पात्र महिला यात्रियों की पहचान और निशुल्क यात्रा की व्यवस्था को सुगम बनाया जा सकेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माता अहिल्याबाई साहस और स्वाभिमान की प्रतीक हैं। इसलिए हमने इस योजना का नाम 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा' योजना नाम दिया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर 27, 28 और 29 अगस्त को महिलाओं को अपने एक सहयात्री के साथ निशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं, इसके बाद 60 वर्ष की उम्र से ऊपर की हर एक महिला को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी।

मानसून में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, IMA ने जारी की एडवाइजरी, दिल्ली में 1,770 से ज्यादा मामले

नई दिल्ली। बिक, देश में फिलहाल H1N1 संक्रमण के मामलों में मौसमी वृद्धि देखी जा रही है। दिल्ली जैसे महानगरों में 1,770 से अधिक लैब से पुष्टि किए गए मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। IMA ने अपनी सलाह में कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की निगरानी के अनुसार, देश में फिलहाल मौसमी इन्फ्लुएंजा ए (H1N1) वायरस ही फैल रहा है। अभी तक वायरस में किसी नए आनुवंशिक बदलाव या म्यूटेशन का पता नहीं चला है। संस्था ने कहा कि मानसून के दौरान H1N1 मामलों में मौसमी बढ़ोतरी सामान्य तौर पर देखी जा सकती है। इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन स्थिति को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सकीय संस्था के अनुसार, H1N1 के ज्यादातर संक्रमण हल्के होते हैं और मरीज समय के साथ ठीक हो जाते हैं। हालांकि, कुछ मामलों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। ऐसे में लक्षणों की निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर समय पर डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। IMA ने विशेष रूप से लोगों को खुद से दवाएं लेने से बचने की सलाह दी है।

सीडीएस चौहान का बड़ा खुलासा : सरगोधा के बाद स्कार्दू पर थी भारत की नजर : चौहान

नई दिल्ली, एजेंसी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सरगोधा को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस पर हमला करने की योजना बनाई थी। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसका खुलासा किया है और बताया कि भारतीय सेनाओं ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान गिलगित-बाल्टिस्तान में स्कार्दू को एक संभावित लक्ष्य के तौर पर चुना था, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ी। चौहान, जो 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय सेना की कमान संभाल रहे थे, ने विवेकानंद इंटरनेशनल फ़ाउंडेशन में 'ऑपरेशन सिंदूर' और उसके बाद की स्थितियों पर बात करते हुए ये बातें कहीं। आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन को याद करते हुए पूर्व CDS चौहान ने कहा, 'एक बार पाकिस्तानियों ने फ़ोन करके कहा कि

वे सुबह करीब 10 बजे बात करना चाहते हैं। एयर चीफ़ ने मुझसे पूछा कि क्या उन्हें सरगोधा पर हमला करना चाहिए, तो मैंने कहा, आगे बढ़िए... मैंने कहा, क्या आप कृपया दो और टारगेट की पहचान कर सकते हैं? तो उन्होंने जो टारगेट पहचाने, उनमें से एक स्कार्दू था। उन्होंने आगे कहा, 'हमने मंजूरी दे दी थी, लेकिन कुछ समय बाद वहां मौसम खराब हो गया और उन्हें अपना रुख बदलकर भोलारी की ओर जाना पड़ा।

चौहान ने यह भी साफ़ किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की किराना हिल्स को 'निशाना नहीं बनाया'; कहा जाता है कि यह इलाका परमाणु सुविधा से जुड़ा है। उन्होंने एयर मार्शल एके भारती का समर्थन किया, जो उस समय वायु सेना में एयर ऑपरेशन्स के डायरेक्टर जनरल (DGAO) थे। भारती ने पिछले साल 12 मई को कहा था, 'हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया, वहां जो कुछ भी है।'

देश में महंगाई की मार और बीजेपी कर रही बेतुकी बात... प्याज, चीनी और तेल की बढ़ती कीमतों पर खरगे का हमला

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 12 साल से भाजपा सरकार है और 'अच्छे दिनों' का आलम ये है कि कभी दाल, कभी सब्जी कभी तेल, कभी चीनी आम आदमी का बजट बिगाड़ देती है।

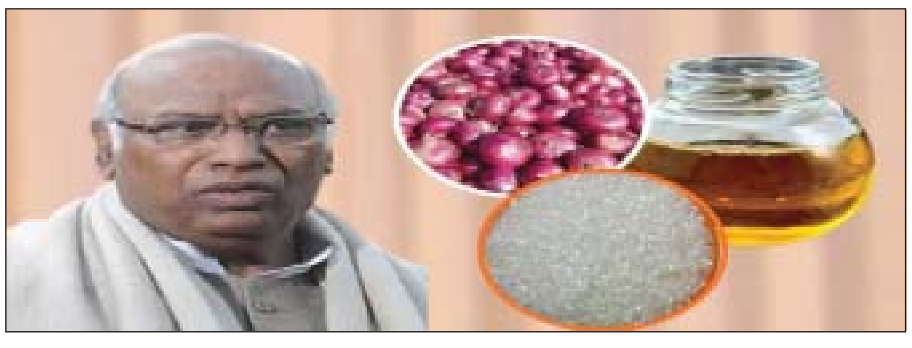

खरगे ने कहा कि देश में महंगाई की मार है लेकिन बीजेपी ध्यान भटकाने वाले स्टंट्स और बेतुकी बातों में उलझाकर अपनी करतूतों से पीछा छुड़ाना चाहती है लेकिन कांग्रेस महंगाई पर सवाल पूछती रहेगी। खरगे ने अपने ट्वीट में प्याज, चीनी, तेल समेत कई चीजों के बढ़ते दामों का जिक्र किया है। खरगे ने इस ट्वीट के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि मोदी सरकार के आने से पहले यानी मई 2013 में किन चीजों की क्या कीमत थी। और अब यानी 2026 में उसकी कीमत क्या है और उसमें कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है। मई 2013 की तुलना में अगस्त 2026 तक रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं।

सबसे ज्यादा मार हरी सब्जियों और बुनियादी खाद्य पदार्थों पर पड़ी है। 13 साल पहले जो टमाटर 17.50 रुपये प्रति किलो मिलता था, वह आज 120 पर पहुंच चुका है। इसी तरह प्याज 217 प्रतिशत और आटा 228 फीसदी महंगा हो गया है।

चीनी, तेल की कीमतें दोगुनी से भी अधिक

दूध, चीनी, तेल और दालों जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें दोगुनी से भी अधिक हो चुकी हैं। खरगे का कहना है कि जब भी जनता इन बुनियादी हकों और महंगाई पर सवाल उठाती है, तो इसे बेतुके बयानों और स्टंट्स की तरफ मोड़ दिया जाता है। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि खोखले दावों से पेट नहीं भरता, जनता को अब ठोस समाधान और राहत की जरूरत है।

कंगना की 'जवानी' पर सवाल, रामदेव को मिला करारा जवाब; विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक

नई दिल्ली, एजेंसी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत और योगगुरु बाबा रामदेव के बीच 'Generation Gutter' बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। कंगना ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे Gen Z युवाओं को लेकर यह टिप्पणी की थी, जिस पर रामदेव ने उनकी जवानी और पुराने कामों पर सवाल उठाए।

रामदेव की टिप्पणी पर कंगना ने इंस्टाग्राम के जरिए तीखा पलटवार किया। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर टिप्पणी को लेकर रामदेव को घेरा और पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार और माफी का भी जिक्र किया। कंगना ने कहा कि उन्हें चरित्र का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है।

कंगना ने रामदेव पर महिलाओं को लेकर मर्यादा की सीमा लांघने का आरोप भी लगाया। वहीं, विवाद बढ़ने के बाद रामदेव ने कहा कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और देश उनके योगदान को जानता है।

इस तरह 'Generation Gutter' से शुरू हुआ विवाद कंगना की जवानी, निजी जिंदगी, चरित्र और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।

बिहार में सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान : 3 नई योजनाओं से महिलाएं बनेंगी 'लखपति दीदी', सशक्त होगा बिहार

पटना, एजेंसी। सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर राज्य सरकार के जोर को रेखांकित करते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के उद्देश्य से तीन प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पंचायतों से लेकर प्रशासन तक महिलाओं की भागीदारी बिहार में समाज की बदलती तस्वीर को दर्शाती है। हाल ही में शुरू किए गए 'पुलिस दीदी' अभियान के तहत, लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। फील्ड ड्यूटी के दौरान उनकी आवाजाही को आसान बनाने के लिए, महिला कर्मियों को लगभग 2,700 स्कूटी और 2,000 से अधिक

मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि वर्तमान में राज्य पुलिस बल में लगभग 40,000 महिला पुलिस कर्मी कार्यरत हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 'डायल 112' हेल्पलाइन के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया समय (रिस्पॉन्स टाइम) घटकर 10 मिनट से कम हो गया है, और प्रशासन का लक्ष्य इसे और कम करके 5-7 मिनट तक लाना है। आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 1.81 करोड़ महिलाएं 'जीविका' (JEEViKA) पहल से जुड़ी हैं, जिनमें से 70 लाख से अधिक 'जीविका दीदियां' सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 43 लाख महिलाएं पहले ही 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं, और अगले दो वर्षों में एक लाख और महिलाओं को इस श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है।

दिल्ली में शुरू हुई लक्ष्मी योजना, महिलाओं के मिले 2,500, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता न ने कही यह बड़ी बात

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को दिखाती है और उन्होंने दोहराया कि दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देना उनकी सरकार का वादा था। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू होने के एक महीने के अंदर ही लगभग 9.5 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। पत्रकारों से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि यह योजना पीएम मोदी के संकल्प को दर्शाती है; असल में, हमने पहले दिन से ही कहा था कि दिल्ली की बहनों को 2,500 रुपये देना हमारा वादा था। आज, जब हम 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को लोगों तक असल रूप में पहुंचा रहे हैं, तो दिल्ली की बहनों को इतना खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।

उन्होंने आगे कहा कि हमने यह योजना 1 अगस्त को शुरू की थी। सिर्फ एक महीने में, लगभग 9.5 लाख बहनों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया। आज के कार्यक्रम के जरिए, हमने इन्हें 2,500 रुपये वाली योजना के तहत पहले 2,500 लाभार्थियों को वेरिफिकेशन और मंजूरी के पत्र बांटे हैं। अगस्त महीने के पैसे 1 सितंबर को उनके खातों में जमा कर दिए जाएंगे। गुप्ता ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सीमा या समय-सीमा नहीं है और महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार आवेदन कर सकती हैं।

यूपी चुनाव से पहले सपा का बड़ा दांव- महिलाओं को 40 हजार रुपये देने का वादा, शुरू होगी स्त्री सम्मान समृद्धि योजना

आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होती जा रही है। राज्य में चुनाव में महिलाओं से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने महिलाओं से जुड़ा बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करेगी, जिसकी रकम 40 हजार रुपये होगी और यह धनराशि हर साल बढ़ेगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि आधी आबादी के बिना देश की तरक्की अधूरी है।

महिलाओं की तरक्की की बात करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आधी आबादी के बिना देश की तरक्की अधूरी है। हम महिलाओं के लिए स्त्री समृद्धि योजना शुरू करेंगे।

पहले हमारी सरकार में जो फैसले लिए गए थे आज भी वे देश और यूपी सरकार के लिए उदाहरण बना हुआ है।

जापानी डेलिगेशन को 1090 सिस्टम दिखाया गया: अखिलेश

उन्होंने कहा कि पिछले दिनों यूपी में जब जापानी डेलिगेशन आया था, तब हमारा बनाया गया 1090 सिस्टम दिखाया गया। ये योजना आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है। हर साल महिलाओं को 40 हजार रुपये दिए जाएंगे। हमने पहले भी लैपटाप बांटे और वो लैपटाप आज भी चल रहे होंगे। किसी का नाम लिए बगैर सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि आज जो लोग कुछ नहीं समझते वो टैबलेट बांटने की बात करते हैं। आज अंगुली घिस दीजिए, तब भी स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा है। बीजेपी के लिए, नारी केवल नारा है। बीजेपी के लोग नारी वंदन की बात करते हैं। बीजेपी को हाथरस की बेटी की याद दिलाइए, कि इन्होंने मां बेटी को जिंदा जलाया था।

बंद स्कूल फिर से खुलेंगे, छात्राओं को लैपटॉप: अखिलेश

समाजवादी पार्टी नेतृत्व की ओर से कहा गया कि राज्य की सत्ता में लौटने पर सपा सरकार आठवीं तक जो स्कूल बंद किए गए, वो फिर से खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए, बनाए गए 1090 को फिर से मजबूत किया जाएगा। पुलिस बल में 33% महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के लिए एंबुलेंस सेवा शुरू होगी। साथ ही इंटर की परीक्षा पास करने वाले छात्राओं को लैपटॉप मिलेंगे। हर जिले में अस्पताल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाए जाएंगे।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव की महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ी कई महिला नेताओं ने अपनी बात रखी। डिंपल यादव ने अपने भाषण में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी राज्य में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करेगी। इस योजना की रकम 40 हजार रुपये होगी। हर साल यह धनराशि बढ़ती जाएगी।

'क्या आरएसएस पर कोई केस है?': प्रियांक खरगे के जवाब पर भाजपा का तंज

बंगलूरू, एजेंसी। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे बुधवार को भाजपा नेता चलवादी नारायणस्वामी के एक सवाल के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ सांप्रदायिक दंगों या किसी अन्य अपराध का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। खरगे का यह बयान विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायणस्वामी के एक सवाल के जवाब में आया है। नारायणस्वामी ने आरएसएस के खिलाफ दर्ज मामलों, सांप्रदायिक दंगों में उसकी भूमिका और उसके रूट मार्च (पथसंचलन) व रोजीना की सभाओं (शाखाओं) के दौरान हुई किसी भी अप्रिय घटना के बारे में जानकारी मांगी थी। खरगे ने विधान परिषद में लिखित जवाब में कहा, 'कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।' भाजपा ने खरगे के इस जवाब का इस्तेमाल उन पर निशाना साधने के लिए किया। खरगे आरएसएस के मुखर आलोचक रहे हैं। इसके साथ ही संगठन की कानूनी स्थिति से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। एक्स पर खरगे का लिखित जवाब पोस्ट करते हुए, नारायणस्वामी ने कहा, 'गृह मंत्री प्रियांक खरगे, जो लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ नफरत, ईर्ष्या और दुश्मनी की राजनीति करते रहे हैं। एक ऐसा संगठन जिसका मूल सिद्धांत देशभक्ति है। गृह मंत्री दस्तावेज खुद सच बयां करते हैं। आरएसएस के खिलाफ गृह मंत्री की पर्दाफाश हो गया है।' विपक्ष के नेता ने खरगे से यह भी पूछा कि जब उनके अपने विभाग ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि कोई मामला या किसी अप्रिय घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वे आरएसएस के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम क्यों करते रहते हैं?

आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष अवसर की मांग, सैकड़ों लोगों ने भरी हुंकार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। शिक्षा, युवाओं के भविष्य, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के अधिकार, सामाजिक एकता और सम्मान के मुद्दों को लेकर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। गौरक्षा वाहिनी उत्तर प्रदेश, नवयुवक दल पार्टी, करणी सेना, क्षत्रिय सभा समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में यूजीसी की नीतियों से लेकर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सुविधाएं देने तथा आर्थिक आधार पर विशेष अवसर की मांग उठाई गई।

कार्यक्रम के दौरान तिलक, तराजू और तलवार नहीं सहेगा अत्याचार का नारा भी गूंजा। वक्ताओं ने कहा कि तिलक ज्ञान और संस्कार, तराजू आर्थिक मजबूती एवं संतुलन और तलवार साहस व आत्मबल का प्रतीक है। उन्होंने इन प्रतीकों को सकारात्मक रूप में लेते हुए ज्ञान, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने पर जोर दिया। गौ रक्षा वाहिनी उत्तर प्रदेश एवं नवयुवक दल के प्रदेश प्रभारी सर्वेश कुमार सिंह ने कहा कि समाज की वास्तविक ताकत संख्या में नहीं, बल्कि ज्ञान, आर्थिक मजबूती और सामर्थ्य में है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति या वर्ग से नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था से है जिसमें आर्थिक कमजोरी के कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने फीस में राहत, छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर यूजीसी की नीतियों में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखने, उच्च शिक्षा में फीस राहत और छात्रवृत्ति बढ़ाने, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग व अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने तथा आर्थिक आधार पर आरक्षण अथवा विशेष अवसर की मांग पर संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप विचार करने की मांग की गई। ज्ञापन में युवाओं के लिए प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का पारदर्शी लाभ और उच्च शिक्षा एवं रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने समेत 10 प्रमुख मांगें रखी गईं। कार्यक्रम में जिला संयोजक उदय प्रकाश मिश्रा, सुभाष सोनकर, प्रदीप कसौंधन, मुकेश कसौंधन, किरण सोनी, राजवीर श्रीवास्तव, बृजेश श्रीवास्तव 'बंटू', पूनम सिंह सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि आर्थिक स्थिति किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी के भविष्य में बाधा नहीं बननी चाहिए और सभी मांगें संवैधानिक व लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष रखी जानी चाहिए।

पहले दिन ही धंस गई करोड़ों की पुलिया

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। शहर की आवास विकास कॉलोनी के मुख्य द्वार से प्रवेश करना इन दिनों लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। नगर पालिका की ओर से करोड़ों रुपये के टेंडर से कराया जा रहा नाले का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन निर्माणाधीन पुलिया के आधे हिस्से से सोमवार को आवागमन शुरू करा दिया गया। रास्ता खुलने के कुछ ही समय बाद पुलिया का हिस्सा धंस गया और एक बाइक सवार की बाइक उसमें फंस गई। गनीमत रही कि बाइक सवार किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। पुलिया के पहले ही दिन धंसने की घटना ने निर्माण की गुणवत्ता और नगर पालिका की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही अधूरी पुलिया पर आवागमन शुरू कराना लोगों की जान जोखिम में डालने जैसा है। आवास विकास कॉलोनी में 500 से अधिक परिवार निवास करते हैं। इसी परिसर में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का मुख्य कार्यालय भी स्थित है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है। पुलिया और नाले के निर्माण के कारण मुख्य रास्ता पहले से ही बदहाल है। बरसात के बाद स्थिति और खराब हो गई है। फिसलन के चलते दोपहिया वाहन सवारों के साथ पैदल आने-जाने वाले लोगों के भी गिरने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन पुलिया का जो हिस्सा आवागमन के लिए खोला गया था, उसकी मजबूती को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे। मार्ग खुलते ही पुलिया के धंसने की घटना ने आशंकाओं को और गहरा कर दिया है। लोगों का कहना है कि यदि इस रास्ते से कोई भारी वाहन गुजरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब नाले और पुलिया का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ था तो अधूरे मार्ग को आवागमन के लिए क्यों खोला गया? क्या मार्ग खोलने से पहले नगर पालिका के संबंधित अभियंताओं ने निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच की थी? यदि जांच की गई थी तो पहले ही दिन पुलिया धंसने की नौबत कैसे आ गई? स्थानीय लोगों ने निर्माण में इस्तेमाल सामग्री, तकनीकी मानकों और गुणवत्ता की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि केवल पुलिया की मरम्मत कराने के बजाय पूरे निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए।

यूपी में वर्दी फिर हुई शर्मसार ! नशे में धुत पीआरडी जवान ने सरेराह किया हाईवोल्टेज ड्रा

आर्यावर्त संवाददाता

कन्नौज। यूपी में वर्दी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। शहर के तिर्वा क्रॉसिंग चौराहे पर मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे ड्यूटी पर तैनात एक प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवान ने शराब के नशे में हंगामा किया। जीटी रोड के बीचों बीच लेट गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर रविशंकर त्रिपाठी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जब पुलिस कर्मियों ने जवान को सड़क से हटाने की कोशिश की, तो वह शांत होने के बजाय पुलिस से ही उलझ गया। पर पुलिस ने सड़क से हटाकर मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा।

ट्रैफिक इंस्पेक्टर रविशंकर त्रिपाठी ने बताया कि पीआरडी जवान राम सिंह यादव अक्सर अपनी ड्यूटी के स्थान को लेकर असंतोष जताता रहता है। हंगामे के दौरान भी वह सही जगह ड्यूटी न लगाए जाने का आरोप लगाकर चिल्ला रहा था।

अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद नशे की आधिकारिक पुष्टि होगी। स्पष्ट किया कि जवान के इस अनुशासनहीन और गैर-जिम्मेदाराना रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीआरडी विभाग को औपचारिक पत्र भी भेजा जा रहा है।

सपा रोजाना बदल रही पीडीए के मायने, जनता में पैदा हो रहा भ्रम-मनोज पाण्डेय

सुल्तानपुर। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पाण्डेय ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी रोजाना पीडीए के मायने बदल रही है। पीडीए का अर्थ लिखते-लिखते डायरी भर गई, लेकिन इसका स्पष्ट अर्थ अभी तक सामने नहीं आ पाया है। सपा का यह रुख भ्रम पैदा करने वाला है। अखिलेश यादव के वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के दावे पर मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सपने देखने का अधिकार सभी को है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष सत्ता में रहते हुए गरीब, कमजोर, युवाओं और किसानों के हित में काम करता तो उसे सत्ता से बाहर नहीं होना पड़ता। चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा

राशन दुकानों पर मिलेंगी बैठने और ठंडे पानी की सुविधाएं

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पाण्डेय बुधवार को सुलतानपुर पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सहित कई सुविधाओं की घोषणा की।

मंत्री ने बताया कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत बुजुर्ग महिलाएं तीर्थयात्रा, दर्शन या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए प्रदेश में कहीं भी रोडवेज बस से बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। यात्रा के लिए आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी को मान्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हित में लगातार कार्य कर रही है। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के साथ प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय और अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है।

कानून व्यवस्था पर मंत्री ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था के चलते अपराध में कमी आई है। उन्होंने कहा कि रोजगार, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कानून व्यवस्था आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। खाद्य एवं रसद मंत्री ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की खाद्यान्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में करीब 17 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ पात्र लोगों को बिना किसी जाति, धर्म या राजनीतिक भेदभाव के दिया जा रहा है। साथ ही अन्नपूर्णा भवनों और कोटे की दुकानों के कोटेदारों के लाभांश में भी वृद्धि की गई है।

वाराणसी में गंगा का जलस्तर स्थिर पर मुश्किलें बरकरार, तटीय इलाकों में बाढ़ का संकट ; नाव संचालन पर रोक

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

वाराणसी। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़त के बाद अब स्थिर हो गया है, लेकिन तटीय इलाकों और घाटों पर बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त बना हुआ है।

केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को गंगा का जलस्तर 68.26 मीटर दर्ज किया गया। बाढ़ के विकराल रूप के कारण दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस चौकी पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है और पानी घाट की ऊपरी सीढ़ियों तक पहुंच गया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने नाव संचालन पर अगले आदेश तक पूरी तरह रोक लगा दी है। स्थानीय नाविकों के अनुसार नावों का परिचालन बंद होने से नौका विहार पूरी तरह ठप है। जल पुलिस प्रभारी सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि सावन माह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जलमग्न घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है और लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को गहरे पानी में न जाने की चेतावनी दी जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें सभी तटवर्ती इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

ईद-ए-मिलाद का पर्व सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया गया

बल्दीराय/सुल्तानपुर। तहसील क्षेत्र बल्दीराय में ईद-ए-मिलादुन्नबी का पर्व शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के इब्राहिमपुर (वलीपुर), पारा बाजार-नन्दौली, कुमासी, बघौना बाजार, कनेहटी, ब्रह्महौली, बहेरी, नरसड़ा सहित विभिन्न गांवों और बाजारों में लोगों ने जुलूस निकालकर अमन, भाईचारे और अनेकता में एकता का संदेश दिया। बहेरी गांव में आयोजित जुलूसे-ए-मिलाद में पड़रे ग्रामसभा के प्रधान प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने सहभागिता करते हुए कार्यक्रम की अगुवाई की। प्रधान सज्जू बेग ने लोगों से सामाजिक समरसता बनाए रखने तथा जनहित और समाजहित को सर्वोपरि रखते हुए पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्व समाज में प्रेम, भाईचारे और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने का अवसर हैं। कार्यक्रम के अंत में मो. अरशद अली ने सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को ईद-ए-मिलाद की मुबारकबाद देते हुए क्षेत्र में अमन-चौन और खुशहाली की कामना की।

गोरखपुर में पति-पत्नी के 'हाई-वोल्टेज' ड्रामे में उड़ी शहर की बिजली, 11KV लाइन पर टांगे कपड़े

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। पति-पत्नी की लड़ाई ने बिजली निगम की बत्ती गुल कर दी। मामला राप्तीनगर उपकेंद्र से जुड़े रामजानकीनगर फीडर क्षेत्र का है। मंगलवार रात 10 अचानक बंद फीडर ट्रिप कर गया। बिजलीकर्मियों ने लाइन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद पेट्रोलिंग शुरू हुई।

इसी दौरान एक जगह 11 हजार वोल्ट की लाइन पर कपड़े लटके मिले। बिजलीकर्मी सीढ़ी लेकर मौके पर पहुंचे। आखिरकार दो घंटे की मशक्कत के बाद आपूर्ति बहाल हो सकी। पता चला कि कुछ देर पहले पति-पत्नी में लड़ाई हुई थी। इसके बाद पति ने पत्नी के कपड़े उठाकर बाहर फेंक दिए थे, जो 11 हजार वोल्ट के तारों पर अटक गए थे।

मंगलवार रात रामजानकीनगर के शिवनगर कालोनी के एक घर में काफी देर से पति-पत्नी के बीच लड़ाई हो रही थी। परिवार के लोग दोनों को समझाने में जुटे थे। अचानक घर की छत से कपड़े फेंके जाने लगे। कई कपड़े एक साथ छत से सड़क पर फेंके गए।

घर के बाहर से रामजानकीनगर फीडर की लाइन गुजरती है। छत से फेंके गए कपड़े लाइन के तार में भी फंस गए। कुछ कपड़े सड़क के किनारे गिरे। जैसे ही तार पर कपड़े फंसे, रामजानकीनगर फीडर बंद हो गया। इससे तकरीबन दो हजार घरों की बिजली कट गई। उमस भरी गर्मी से परेशान उपभोक्ताओं ने उपकेंद्र पर सूचना दी तो फाल्ट की तलाश शुरू कराई गई।

पेट्रोलिंग करते हुए कर्मचारी शिवनगर कालोनी पहुंचे तो वहां तार पर कपड़े लटके देख हैरान रह गए। उन्होंने इसकी सूचना अभियंताओं को दी और कपड़े उतारने के लिए सीढ़ी मंगाई। इसके बाद सीढ़ी मंगाकर काफी मशक्कत कर कपड़े हटाए गए। तकरीबन दो घंटे बाद बिजली दी जा सकी।

बिजली कटौती पर विधायक ने अधिकारियों को लगाई फटकार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती और विद्युत आपूर्ति की खराब व्यवस्था को लेकर सुलतानपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने बुधवार को विद्युत विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। विधायक दरियापुर स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की बिजली व्यवस्था की जानकारी ली। विधायक ने कहा कि लगातार बिजली कटौती से क्षेत्र की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं। जर्जर और पुराने बिजली के तारों को प्राथमिकता के आधार पर बदलने के साथ ही तकनीकी खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बिजली फाल्ट की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, वहां तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। विधायक ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि विद्युत आपूर्ति के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक के कड़े तेवर के बाद विद्युत अधिकारियों ने समस्याओं के शीघ्र समाधान और आपूर्ति व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया। विनोद सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है और बिजली व्यवस्था को लेकर वह लगातार अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान अधीक्षण अभियंता विपुल कुमार जैन, अधिशासी अभियंता सुलतानपुर अश्वनी कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता बल्दीराय शशांक शुक्ला, अधिशासी अभियंता जयसिंहपुर संजय कुमार यादव, अधिशासी अभियंता लंभुआ रितेश्वर बंधु, अधिशासी अभियंता कादीपुर प्रशांत कुमार समेत विद्युत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मथुरा में विकास को मिली रफ्तार : 46 करोड़ की लागत से बनेंगी 29 नई सड़कें, शासन से पहली किस्त जारी

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। लोक निर्माण विभाग ने इस वित्तीय वर्ष जिले के पांचों विधायकों के प्रस्तावों पर शासन ने मुहर लगा दी है। शासन को भेजी गईं 46 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत कर ली गई हैं और पहली किस्त के रूप में प्रस्तावों की एक तिहाई धनराशि करीब 15 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दी है। मांट क्षेत्र में 160 लाख से सुहागपुर से चांदपुर कलां मार्ग, 163 लाख से कराहरी मार्ग सेमरजा होते हुए दुनैटिया मार्ग का नवनिर्माण 105 लाख से गांव शल्ल से लालपुर मार्ग, 140 लाख से गांव विवावली से अड्डा मार्ग, 111 लाख से नगला मौजी से नगला बरी तक का मार्ग, 111 लाख से मथुरा-वृंदावन-मांट-नौहझील मार्ग से मिलक मार्ग और 184 लाख रुपये से नरवै हंसी से चूरा हंसी मार्ग का नवनिर्माण होगा।

पांचों विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर होंगे कार्य

मथुरा क्षेत्र में 155 लाख से महोली से मुकंदपुर मार्ग, 190 लाख से गांव नगला विहारी का मार्ग, वृंदावन में 98 लाख से प्रियाकांतजू मंदिर के बराबर से अल्हैपुर चौराहा तक मार्ग का निर्माण होगा। छाता में 147 लाख से कामर से राजस्थान सीमा तक मार्ग बनेगा, यह ब्रज चौरासी कोस में है। 260 लाख से अकबरपुर शेरगढ़ रोड से आरटीएल ड्रेन पटरी मार्ग, 194 लाख से पिसावा से रहेड़ा मार्ग, 261 लाख से गुहारी से भदावल मार्ग, 211 लाख से देवपुरा से ढहरौली मार्ग बनेगा।

शासन ने पहली किस्त के रूप में एक तिहाई धनराशि अवमुक्त की

गोवर्धन में 179 लाख से गांव जानू से पास्ता मार्ग राजस्थान सीमा तक, 197 लाख से मासूम नगर से तारसी संपर्क मार्ग, 139 लाख रुपये से उस्फार से मुकंदपुर मार्ग, 283 लाख से बाटी से कोटा मार्ग, 115 नवीपुर से ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा तक का मार्ग, 166 जनसुटी से बसई संपर्क मार्ग बनेगा।

बलदेव में इन सड़कों का होगा निर्माण

दूसरी ओर बलदेव में 93 लाख से सराय दाऊद के बाग से बंबे के पुल तक, 92 लाख से महावन किशनपुर से नगला भंभू तक मार्ग, 201 लाख से बल्टीकरी मार्ग से शहीद मूर्ति तक मार्ग, 167 लाख से फतिहा मोड़ से महुअन होते हुए कुरकंदा मार्ग, 193 लाख से मड़ौरा ततरौता मार्ग से बुर्जदाता मार्ग, 96 लाख से राष्ट्रीय राजमार्ग से नगला बंजारा तक, 104 लाख से राया सादाबाद मार्ग से खजूरी मछली गढ़ी तक और 89 लाख से नगला सेवा से नूरपुर बंबा तक मार्ग का मार्ग बनेगा।

प्रयागराज में 27 अगस्त से बारिश में कमी आएगी, एक सप्ताह उमस करेगी परेशान ; सितंबर में फिर अच्छी वर्षा होगी

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। मानसून की सक्रियता के बीच प्रयागराज में मौसम का मिजाज आज बुधवार को भी बदला-बदला रहा। 25 अगस्त की रात से सुबह तक रुक-रुककर बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जारी रहा। हालांकि दिन निकलने के बाद बारिश थम गई और कई दिन बाद धूप निकली। आसमान में बादलों और सूर्य की लुकाछिपी चलती रही। वातावरण में नमी अधिक होने व धूप के कारण उमस का असर भी बना रहा। लोगों को गर्मी से पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी।

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान प्रयागराज में 21.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बुधवार सुबह आर्द्रता 92 प्रतिशत रही, जिससे वातावरण में नमी काफी अधिक महसूस की गई। वहीं न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बुधवार को भी सामान्यतः आसमान में बादल छाए रहने तथा एक-दो बार बारिश अथवा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

अगस्त में अब तक 630 मिमी वर्षा हो चुकी

अगस्त में अब तक प्रयागराज में करीब 630 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से जहां मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा। वहीं शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आ रही है। बारिश के बाद सड़कों और गलियों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कल से बदलेगा मौसम, बढ़ेगी उमस

मौसम विभाग के अनुसार कल 27 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने लगेगी। 27 और 28 अगस्त को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद 29 और 30 अगस्त को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहने का अनुमान है और अधिकतम तापमान बढ़कर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

सितंबर में भी होगी अच्छी बारिश

बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ अगले करीब एक सप्ताह तक उमस लोगों को परेशान कर सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने सितंबर में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में मानसून की पूरी तरह विदाई से पहले प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं।

डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश पर तंज, बोले- सपा के मुंह से महिला सुरक्षा-सम्मान की बात महज छलावा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के मुंह से महिला सुरक्षा-सम्मान की बात महज छलावा है। यूपी ने 2012-17 के दरम्यान सपा की गुंडागर्दी, अपराध, माफिया, दंगाइयों और भ्रष्टाचारियों के संरक्षण वाली राजनीति न केवल देखी है, बल्कि काफी हद तक सही भी है।

उन्होंने कहा कि यह साफ है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2027 से 2047 तक यूपी की सत्ता और उनके दिल्ली वाले गार्जियन कांग्रेस के जेन-जी नेता राहुल गांधी को 2049 तक देश की सत्ता मिलने वाली नहीं है। दोनों भविष्य के नाम पर फर्जी वादे बेच रहे हैं। सपा का पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी की हकीकत यूपी की महिलाएं बेहतर तरीके से समझती हैं और वे सपा की चाल, जाल और झांसे में नहीं आएंगी।

अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने राष्ट्रीय महिला समानता दिवस के अवसर पर आयोजित संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके तहत समाजवादी सरकार बनने पर आधी आबादी को पूरी आजादी मिलेगी। उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। गरीब महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये दिए जाएंगे। छात्राओं को इंटर पास होने के बाद लैपटॉप और साइकिल दी जाएगी। महिलाओं की सरकारी बसों में यात्रा मुफ्त होगी। छात्राओं को मेट्रो सफर मुफ्त होगा।

पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार में बंद किए सभी 26 हजार प्राइमरी स्कूल फिर खोले जाएंगे। सरकारी स्कूलों में फीस माफ और प्राइवेट में फीस हाफ होगी। न्यूट्रिशन मिशन योजना फिर शुरू की जाएगी। ऑगनबाड़ी केंद्रों को ठीक किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि स्त्री सम्मान समृद्धि योजना आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आए जापान के डेलीगेशन को सरकार ने उसी 1090 हेल्पलाइन को दिखाया जो सपा सरकार में बनाया गया था। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। सपा सरकार की योजनाओं का असर है, जो तकनीकी के बारे में कुछ नहीं जानते वे टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। भाजपा के लिए नारी केवल नारा बनकर रह गया है। सभी लोग जानते है कि महिला आरक्षण बिल संसद में पास होकर कानून बन गया है। हम चाहते है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ही इसे लागू किया जाए।

सपा फिर लेकर आई झूठे वादों का पिटारा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी की नई घोषणाओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पुराने पाप और नाकामियों को छिपाने के लिए सपा फिर 'झूठे वादों का पिटारा' लेकर जनता के बीच आई है। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठते थे, जबकि आज पार्टी महिला सम्मान, सुरक्षा और विकास की बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता सपा की पुरानी वादाखिलाफी भूली नहीं है और अब खोखली घोषणाओं व चुनावी लॉलीपॉप से उसे बहकाना संभव नहीं। चौधरी ने अखिलेश यादव की महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देने की घोषणा को महिला वोटरों को लुभाने का प्रयास बताया। उन्होंने सवाल किया कि सपा सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं होती थी। साथ ही पूछा कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की पहल का सपा ने विरोध क्यों किया।

पंकज चौधरी का सपा पर हमला, बोले- पुराने पाप और नाकामियां छिपाने को फिर लाई झूठे वादों का पिटारा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी की नई घोषणाओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपने पुराने पाप और नाकामियों को छिपाने के लिए सपा एक बार फिर झूठे वादों का पिटारा लेकर जनता के सामने आई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सपा महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बड़े-बड़े वादे कर रही है, लेकिन जनता उसके पुराने शासन और वादाखिलाफी को भूली नहीं है।पंकज चौधरी ने कहा कि जिस समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठते थे, वही पार्टी आज महिला सम्मान, सुरक्षा और विकास की बातें कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि सत्ता में रहते हुए महिलाओं की सुरक्षा, बेहतर अस्पताल और कॉलेज जैसी सुविधाओं के लिए सपा सरकार ने ठोस कदम क्यों नहीं उठाए।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देने की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केवल चुनाव से पहले घोषणाएं करने से महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी।उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती थी तथा अपराधियों और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त दबंगों के हौसले बुलंद थे। उन्होंने दावा किया कि उस समय थानों में पीड़ित महिलाओं की शिकायतों पर भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती थी।

• संक्षेप •

मानकनगर क्षेत्र में नहर के रेगुलेटर में मिले दो शव, शिनाख्त के प्रयास जारी

लखनऊ। थाना मानकनगर क्षेत्र के कनौसी पुल के पास नहर के रेगुलेटर में बुधवार सुबह दो शव फंसे होने की सूचना मिली। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नहर से बाहर निकलवाया।पुलिस के अनुसार दोनों शव पुरुषों के हैं। मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। प्रथम दृष्टया एक मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष तथा दूसरे की उम्र करीब 20 वर्ष प्रतीत हो रही है। करीब 20 वर्षीय युवक के दाहिने हाथ पर 'महाकाल' लिखा हुआ टैटू बना है। पुलिस इसी पहचान चिह्न के आधार पर भी मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।पुलिस ने दोनों शवों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के बाद मोर्चरी भेज दिया है। मृतकों की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के साथ अन्य आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

डीसीएम और पल्सर की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार की मौत

लखनऊ। थाना क्षेत्र में लखनऊ-हरदोई रोड पर मोटी नीम के पहले बुधवार दोपहर करीब एक बजे डीसीएम और पल्सर मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार अकीक अहमद पुत्र मो. अहमद, निवासी ग्राम मऊ, थाना मोहनलालगंज, गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक शैलेष प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर जांच के दौरान पता चला कि डीसीएम वाहन संख्या UP 32 EN 9724 और पल्सर मोटरसाइकिल संख्या UP32 MW 0680 के बीच टक्कर हुई थी।गंभीर रूप से घायल अकीक अहमद को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलिहाबाद भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार अकीक अहमद मोहनलालगंज से मलिहाबाद जा रहे थे। हादसे की सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए।पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा करा दिया है। डीसीएम चालक की तलाश की जा रही है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार परिजनों से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल पर शांति एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

गैर जमानती वारंट में वांछित अभियुक्त सुनील कुमार गिरफ्तार

लखनऊ। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कमिश्नरेट लखनऊ की कृष्णानगर पुलिस ने न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के मामले में वांछित अभियुक्त सुनील कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।पुलिस आयुक्त लखनऊ तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो. मुश्ताक के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली वसंथ कुमार के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर प्रद्युमन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार न्यायालय से वाद संख्या 123047/23, थाना कृष्णानगर, लखनऊ से संबंधित एक गैर जमानती अधिपत्र जारी किया गया था। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सुनील कुमार पुत्र सोनेलाल, निवासी सैनी निवास, आसाराम बाबू रोड आश्रम, मानसनगर, उम्र करीब 36 वर्ष को गिरफ्तार किया।गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना कृष्णानगर की पुलिस टीम शामिल रही।

लखनऊ जंक्शन पर स्वास्थ्य जांच शिविर, 70 कर्मचारियों और सफाई मित्रों की हुई जांच

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमेश चन्द्र के निर्देशन एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय तिवारी के नेतृत्व में लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों एवं सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की जांच की गई।शिविर के दौरान कुल 70 कर्मचारियों एवं सफाई मित्रों की स्वास्थ्य जांच की गई। जांच में 14 कर्मचारी नए उच्च रक्तचाप से ग्रसित पाए गए, जबकि एक कर्मचारी पहले से उच्च रक्तचाप से पीड़ित मिला। इसी प्रकार एक कर्मचारी में मधुमेह का नया मामला सामने आया, जबकि एक कर्मचारी पहले से मधुमेह से पीड़ित पाया गया।अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय तिवारी ने कर्मचारियों एवं सफाई मित्रों को जीवनशैली में आवश्यक बदलाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तनाव प्रबंधन और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने के महत्व पर प्रकाश डाला।उन्होंने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच से बीमारियों की समय रहते पहचान की जा सकती है और उचित उपचार शुरू किया जा सकता है। स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य रेल कर्मचारियों एवं सफाई मित्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा संभावित बीमारियों की समय रहते पहचान कर उपचार सुनिश्चित करना रहा।इस अवसर पर डॉ. रंजना पाटनी, पैरामेडिकल स्टाफ सहित रेलकर्मी उपस्थित रहे।

बादशाहनगर मंडल चिकित्सालय में निकली स्वच्छता रैली

लखनऊ। महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे के निर्देशानुसार स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता अभियान के तहत बादशाहनगर स्थित मंडल चिकित्सालय में स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमेश चंद के निर्देशन एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनोद पाठक के नेतृत्व में आयोजित रैली में चिकित्सालय के मरीजों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।रैली के दौरान लोगों से कूड़ा-कचरा इधर-उधर न फेंककर निर्धारित कूड़ेदान में डालने, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक का प्रयोग न करने तथा कचरे को अलग-अलग करके उसके उचित निस्तारण की अपील की गई। रैली में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई रखने का संदेश दिया गया।

रक्षाबंधन पर महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा, 27 से 29 अगस्त तक रोडवेज व सिटी बसों में नि :शुल्क यात्रा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की माताओं, बेटियों और बहनों को विशेष उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा की। मुख्यमंत्री के अनुसार महिलाओं के लिए 27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। निगम की बसों में महिला यात्री अपने साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा करा सकेंगी।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा' का शुभारंभ किया और विशेष बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं ने निःशुल्क यात्रा की।इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बारिश के बीच विशेष बसों को रवाना किया। बसों में बैठी महिलाओं ने निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर महिलाओं का अभिवादन किया और उनके साथ सेल्फी ली।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा' के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को स्मार्ट कार्ड प्रदान किए। इसके साथ ही महिलाओं को उपहार स्वरूप बैग, साड़ी और मिठाई भी भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से संवाद कर उनका हालचाल जाना और सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।मुख्यमंत्री के हाथों उपहार प्राप्त करने वाली महिलाओं में राजरानी, गणेश देवी, कलावती, मिठाना, प्रभुदेई, शम्मी, शांति देवी, मंजूलता, शिवकली, द्रौपदी और मीरा सहित अन्य महिलाएं शामिल रहीं।

किराना दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने वाले दो गिरफ्तार, बाल अपचारी भी संरक्षण में

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। थाना काकोरी पुलिस ने किराना दुकान का शटर तोड़कर नकदी और सामान चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी संरक्षण में लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया किराना सामान बरामद किया गया है।पुलिस के अनुसार 13 जुलाई 2026 को राजेन्द्र गुप्ता निवासी सरोसा भरोसा, थाना पारा ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दुकान का शटर तोड़कर करीब 40 हजार रुपये नकद और परचून का सामान चोरी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर घटना के खुलासे के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई थीं।25 अगस्त को काकोरी पुलिस घुरघुरी तालाब के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में शामिल

तीन व्यक्ति चोरी किए गए किराना सामान के साथ असरखेड़ा की ओर से मोहान रोड स्थित एक स्कूल के पास खड़े हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दीपांशु पुत्र श्रीराम जी पाण्डेय, निवासी निसारूपुर, थाना इटियाथोक, गोण्डा, हाल निवासी असरखेड़ा, काकोरी, उम्र करीब 19 वर्ष, अनिकेत पुत्र सजीवन पाल, निवासी ईंटगांव, थाना काकोरी, उम्र करीब 19 वर्ष तथा करीब 16 वर्षीय बाल अपचारी को पकड़ लिया।तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार का किराना सामान बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 13 जुलाई की रात उन्होंने एक साथ मिलकर पुरैना मोड़, मोहान रोड के पास स्थित किराना दुकान का शटर तोड़कर चोरी की थी। बरामदगी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दीपांशु और अनिकेत को रात करीब 9:42 बजे गिरफ्तार किया गया, जबकि बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो पेटी क्लीनिक प्लस शैम्पू, करीब आठ किलोग्राम छोहारा, गोमती मसाला 10 पैकेट, राजश्री मसाला पांच पैकेट, 500 ग्राम दालचीनी, एक किलोग्राम मखाना, एसएनके मसाला 10 पैकेट, स्टार ब्रांड बीड़ी दो पैकेट, डव शैम्पू पांच लड़ी, करीब डेढ़ किलोग्राम काजू, कमलापसंद मसाला पांच पैकेट, सुपरफास्ट तंबाकू पांच पैकेट और करीब दो किलोग्राम धनिया बरामद किया है।पुलिस के अनुसार बाल अपचारी के खिलाफ थाना काकोरी में मुकदमा संख्या 84/2026 धारा 70(2), 115(2), 351(3) बीएनएस तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज है। वहीं अभियुक्त दीपांशु के खिलाफ थाना काकोरी में मुकदमा संख्या 232/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 117(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज है।कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश चन्द्र राठौर, उपनिरीक्षक छत्रजीत सिंह, उपनिरीक्षक अभिमन्यु सिंह, उपनिरीक्षक दयानन्द तिवारी, कांस्टेबल गौरव भदौरिया और कांस्टेबल देवेन्द्र कुमार लवानियां शामिल रहे।

ऑपरेशन डिजिटल कवच' से साइबर ठगों पर शिकंजा, 2.40 करोड़ रुपये की धनराशि होल्ड

लखनऊ। पुलिस आयुक्त के निर्देशन एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में कमिश्नरेट लखनऊ क्राइम ब्रांच द्वारा डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली साइबर ठगी के खिलाफ 'ऑपरेशन डिजिटल कवच' चलाया जा रहा है। अभियान के तहत साइबर ठगी की शिकायत मिलते ही तकनीकी साक्ष्यों, बैंकिंग लेन-देन और धन के प्रवाह का विश्लेषण कर अपराधियों तक पहुंचने के साथ ठगी की धनराशि को तत्काल होल्ड अथवा लियन कराने और पीड़ितों को धनराशि वापस कराने की कार्रवाई की जा रही है।अभियान के तहत 1 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक साइबर सेल द्वारा 2,40,56,807 रुपये की धनराशि होल्ड अथवा लियन कराई गई, जबकि 16,97,462.72 रुपये पीड़ितों को वापस कराए गए। इसके अतिरिक्त साइबर थाना द्वारा 24 लाख रुपये की धनराशि की वापसी कराई गई।

बीबीएयू में 'लीन स्टार्ट-अप एवं न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद' विषय पर विशेष सत्र आयोजित

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में 'लीन स्टार्ट-अप एवं न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद/व्यवसाय' विषय पर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को स्टार्ट-अप, नवाचार, उद्यमिता तथा न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद की अवधारणा से परिचित कराना और उनके अभिनव विचारों को व्यावहारिक व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना रहा।कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के रणनीति, नवाचार एवं उद्यमिता विभाग के प्रोफेसर प्रो. मनोज जोशी, संस्थान नवाचार परिषद के अध्यक्ष प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा, स्कूल ऑफ फिजिकल एंड डिसीजन साइंसेज के अधिष्ठाता प्रो. सुरिन्दर कुमार, सांख्यिकी विभागाध्यक्ष प्रो. सुभाष कुमार यादव, प्रो. मधूलिका दुबे एवं कार्यक्रम समन्वयक डॉ. राहुल वार्ष्णेय उपस्थित रहे।प्रो. मनोज जोशी और प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा ने विद्यार्थियों को समस्या की पहचान, ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने, न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद विकसित करने, बाजार से प्रतिक्रिया प्राप्त करने तथा निरंतर सुधार के माध्यम से स्टार्ट-अप को विकसित करने की प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने प्रतिभागियों को अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने के साथ-साथ बाजार की वास्तविक आवश्यकताओं को समझने पर जोर दिया।इस अवसर पर प्रो. सुरिन्दर कुमार, प्रो. सुभाष कुमार यादव एवं प्रो. मधूलिका दुबे ने विषय की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में डॉ. अमित कुमार मिश्रा, डॉ. मीनाक्षी मिश्रा एवं डॉ. प्रयास शर्मा सहित विभाग के अन्य संकाय सदस्यों की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। संकाय सदस्यों ने शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता की।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों के साथ संवादात्मक प्रश्नोत्तर एवं चर्चा सत्र आयोजित किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने अपने नवाचार संबंधी विचारों एवं जिज्ञासाओं को विशेषज्ञों के साथ साझा किया। उन्हें 'निर्माण-मापन-अधिगम' दृष्टिकोण अपनाने तथा उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया एवं आंकड़ों के आधार पर अपने उत्पाद अथवा व्यवसाय मॉडल में निरंतर सुधार करने के लिए प्रेरित किया गया।यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, नवाचार, उद्यमशीलता और समस्या-समाधान की क्षमता विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रहा।

निषाद समाज के अपमान का आरोप लगाकर कांग्रेस का भाजपा सरकार पर हमला, अजय राय बोले- 2027 में जनता देगी जवाब

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने बुधवार को प्रेसवार्ता में भाजपा पर निषाद समाज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में भाजपा समर्थित लोगों द्वारा निषाद समाज के नेताओं और समाज की माताओं-बहनों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है।अजय राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद के साथ एक समाचार चैनल की लाइव बहस के दौरान राजू दास द्वारा कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग और धमकी दी गई, लेकिन अब तक उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इससे यह संदेश जाएगा कि संबंधित व्यक्ति को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में निषाद समाज भाजपा को उसके कार्यों का जवाब देगा।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह दबाव में झुकने वाले नहीं हैं और लगातार संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर हुए कथित उत्पीड़न और कानूनी कार्रवाई का उल्लेख करते हुए भाजपा सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए।अजय राय ने प्रदेश में बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ सामने आए अपराधों का उल्लेख करते हुए सरकार से सवाल किया कि ऐसी घटनाओं में अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने चकिया, जौनपुर, गाजियाबाद और गोरखपुर में बच्चियों के साथ कथित दुष्कर्म एवं हत्या की घटनाओं का हवाला देते हुए कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए।कांग्रेस नेता राम निहाल निषाद ने कहा कि उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। उन्होंने भाजपा पर निषाद समाज के पारंपरिक भोजन और संस्कृति को लेकर सवाल उठाने तथा समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने भगवान राम और गुहराज निषाद के ऐतिहासिक संबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि निषाद समाज का धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से गहरा संबंध रहा है।राम निहाल निषाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में निषाद समाज को तालाब, नौका घाट, बालू घाट और जमीन के पट्टे दिए गए थे, जबकि भाजपा सरकार ने इन्हें छीनने का काम किया। उन्होंने निषाद समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि समाज के अधिकारों के लिए प्रभावी संघर्ष किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के मामले में राजू दास सार्वजनिक रूप से माफी मांगें तथा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर निषाद समाज का आंदोलन जारी रहेगा। राम निहाल निषाद ने कहा कि राहुल गांधी संविधान, गरीबों, वंचितों और पिछड़ों के अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बनने पर निषाद समाज के अधिकार वापस दिलाने का प्रयास किया जाएगा।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि सभी माताओं का सम्मान करना उनके संस्कार का हिस्सा है।

अंतरिक्ष में भारत की निजी शक्ति एवं वैज्ञानिक सामर्थ्य की उड़ान

भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल सरकारी संस्थानों और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह गई है। यह यात्रा आज नवाचार, उद्यमिता, युवा प्रतिभा, निजी पूंजी और वैश्विक महत्वाकांक्षा के ऐसे संगम में बदल रही है, जिसने भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में एक नई गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी सहभागिता के द्वार खोलने का निर्णय इसी परिवर्तन का निर्णायक पड़ाव है। कभी जिस अंतरिक्ष क्षेत्र को लगभग पूरी तरह सरकारी नियंत्रण और संस्थागत सीमाओं के भीतर देखा जाता था, आज वहां सैकड़ों नवोदित उद्यम अपने सपनों, तकनीक और साहस के साथ नई संभावनाओं का आकाश तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय निजी अंतरिक्ष उद्यमियों से संवाद कर उन्हें प्रेरित करना केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की दिशा का उद्घोष है। इसमें उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ भारत को विश्व की अंतरिक्ष प्रतिभा, निवेश और उद्यमिता का आकर्षण-केंद्र बनाने का सपना प्रस्तुत किया, वह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का भी संकेत है। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का इतिहास अपने आप में असाधारण है। सीमित संसाधनों के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जिस वैज्ञानिक अनुशासन, आत्मनिर्भरता और संकल्प का परिचय दिया, उसने दुनिया को चकित किया है। आर्यभट्ट से प्रारंभ हुई यात्रा मंगलयान तक पहुंची, चंद्रयान ने चंद्रमा के रहस्यों को समझने की भारतीय क्षमता सिद्ध की और चंद्रयान-3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रूवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बनाकर इतिहास रचा। यह उपलब्धि केवल एक वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, यह भारतीय प्रतिभा, तकनीकी आत्मविश्वास और असंभव को संभव करने की राष्ट्रीय क्षमता का प्रमाण थी। मंगलयान ने कम लागत में अंतरग्रहीय अभियान की सफलता से दुनिया को भारत की वैज्ञानिक दक्षता का परिचय दिया। आदित्य-एल1 ने सूर्य के अध्ययन की दिशा में भारत की महत्वाकांक्षा को नई ऊंचाई दी। अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति की तैयारी से जुड़ा गगनयान अभियान भारत की अगली बड़ी छलांग का संकेत है। इस पूरी यात्रा ने यह स्पष्ट किया है कि भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान में केवल उपलब्धियों का अनुकरण करने वाला देश नहीं, बल्कि नए मानदंड स्थापित करने की क्षमता रखने वाला राष्ट्र है।

इस उपलब्धि की अगली स्वाभाविक कड़ी निजी क्षेत्र की भागीदारी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद भारत में लगभग 440 अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी नवोदित उद्यमों का उभरना इस परिवर्तन की गहराई को दर्शाता है। इनमें कुछ उपग्रह निर्माण में लगे हैं, कुछ प्रक्षेपण यानों की तकनीक विकसित कर रहे हैं, कुछ अंतरिक्ष आधारित आंकड़ों के विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पृथ्वी अवलोकन, संचार, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन जैसी अत्याधुनिक दिशाओं में काम कर रहे हैं। स्काईरूट एयरोस्पेस ने निजी क्षेत्र के रॉकेट प्रक्षेपण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है, जबकि अग्निकुल कॉसमॉस ने स्वदेशी तकनीक और आधुनिक निर्माण पद्धतियों के माध्यम से यह दिखाया है कि भारतीय निजी उद्यम अंतरिक्ष प्रक्षेपण के कठिन क्षेत्र में भी अपनी जगह बना सकते हैं। ये प्रयास उस मानसिकता को बदल रहे हैं जिसमें अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों का क्षेत्र माना जाता था। अब यह युवा उद्यमियों के लिए रोजगार, अनुसंधान, निवेश और वैश्विक व्यापार का नया क्षेत्र बन रहा है। इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अंतरिक्ष अब केवल आकाश में उपलब्धियों का विषय नहीं, बल्कि धरती पर जीवन को बेहतर बनाने का साधन भी बन रहा है। उपग्रह आधारित सेवाएं कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, फसल की निगरानी करने, जल संसाधनों की पहचान, मौसम की सटीक जानकारी देने, मछली पालन, वन संरक्षण और आपदा प्रबंधन में उपयोगी हो सकती हैं। बाढ़, चक्रवात, सूखा और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय अंतरिक्ष से प्राप्त सूचनाएं राहत और बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में संचार तथा डिजिटल सेवाओं के विस्तार में भी अंतरिक्ष तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब केवल वैज्ञानिक गौरव का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास का शक्तिशाली माध्यम बन रहा है।

स्कूलों को कर दीजिए बरबाद फिर सारी समस्या समाप्त

स्कूली शिक्षा का निजीकरण बहुत पहले हो चुका है और अब भी काफी स्कूल हैं, जो बहुत अच्छे हैं। वहां से पढ़ाई करके जो छात्र निकल रहे हैं और कॉलेज पहुंच रहे हैं

हरिशंकर व्यास

जंतर मंतर पर 'जेन जी' का आंदोलन हुआ और सरकार बैकफुट पर आई तो उसके बाद आरएसएस में भी इसकी चर्चा शुरू हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि नौजवान इतने नाराज हैं। तब संघ के एक पदाधिकारी ने एक ऐसे बौद्धिक से बात की, जो राइटविंग के हैं लेकिन तार्किक विचार रखते हैं और वास्तविक अर्थों में बौद्धिक हैं। उनसे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि नई पीढ़ी के युवा इतने नाराज हैं और सार्वजनिक रूप से ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, जिनके बारे में कभी कल्पना नहीं की गई थी। उनका जवाब था, 'आपने कॉलेज बरबाद कर दिए, यूनिवर्सिटीज बरबाद कर दी, तकनीकी संस्थान बरबाद कर दिए, लेकिन स्कूल अभी तक बरबाद नहीं कर पाए हैं। स्कूलों को बरबाद कर दीजिए फिर सारी समस्या समाप्त हो जाएगी।

यह बात उन्होंने तंज के अंदाज में कही। उनका कहना था कि स्कूली शिक्षा का निजीकरण बहुत पहले हो चुका है और अब भी काफी स्कूल हैं, जो बहुत अच्छे हैं। वहां से पढ़ाई करके जो छात्र निकल रहे हैं और कॉलेज पहुंच रहे हैं उनके सामने अचानक शून्य आ जा रहा है। न फैकल्टी अच्छी है, न वाइस चांसलर अच्छे हैं, न रिसर्च की सुविधा अच्छी है, न लाइब्रेरी अच्छी है और किसी तरह से वहां एडजस्ट करें तो परीक्षा की पूरी व्यवस्था प्रदूषित हो गई है। वहां उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू होता है। इसी का प्रकटीकरण जंतर मंतर पर हुआ या सोशल मीडिया में भी 'जेन जी' की नाराजगी के रूप में हो रहा है। इसका उपाय यही है कि स्कूली शिक्षा के स्तर पर ही उनकी पढ़ाई लिखाई खराब कर दी जाए तो वे आगे भी शिकायत नहीं करेंगे।

सो प्रधानमंत्री, संघ प्रमुख और केंद्र सरकार के मंत्रियों और राज्यों के नेताओं को पहले तो यह समझना होगा कि छात्र और युवा किस बात से नाराज हैं? वे इस बात से नहीं नाराज हैं कि उनको ठीक तरीके से समझा नहीं जा रहा है। वह समस्या हर पीढ़ी के साथ होती है। वे नाराज इसलिए हैं क्योंकि शिक्षा और परीक्षा दोनों का भ_ा बैठ गया है। कोई भी परीक्षा बिना त्रुटि के नहीं हो रही है। उनका फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर है कि नौकिरयों की संख्या लगातार कम होती जा रही है।

वैकेंसी नहीं आ रही है और आ भी रही है तो उसे भरने की प्रक्रिया इतनी लंबी हो जा रही है कि छात्रों की उम्र निकल जा रही है। हर दूसरी या तीसरी परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। हर दूसरी या तीसरी परीक्षा में परीक्षा केंद्रों पर सेटिंग हो रही है, ओएमआर शीट में गड़बड़ी हो रही है, उत्तर पुस्तिकों की जांच में धांधली हो रही है और कई जगह तो सीधे नौकरी बेच दी जा रही है। छात्रों की इस बात की नाराजगी है कि न तो शिक्षा का कैलेंडर ठीक से चल रहा है और न परीक्षा का कोई कैलेंडर है। ज्यादातर परीक्षाओं में देरी हो रही है और अभ्यर्थियों की उम्र निकल जा रही है। इस बात को समझने की बजाय हर व्यक्ति उनको ज्ञान देने में लगा है या उनकी भाषा बोल कर उनको खुश करने में लगा है। सिरदर्द के इलाज के लिए सरकार के लोग उंगली पर बैंड एड लगा रहे हैं। मंत्री संसद में खड़े होकर 'फोमो', 'एमआईए' और 'डेलुलु' जैसे शब्द बोल कर समझ रहे हैं कि इससे नौजवान खुश हो जाएंगे और शिक्षा व परीक्षा की गड़बड़ियों को भूल जाएंगे।

संकट शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था में आई गड़बड़ियों का है। इसकी शुरुआत 2014 में उसी दिन हो गई थी, जिस दिन नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। सोचें, वे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की रिप्लेसमेंट थीं! भाजपा की आखिरी सरकार यानी 1999 से 2004 के बीच वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद भाजपा को सरकार बनाने का मौका 2014 में मिला तो स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया। इससे शिक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता, प्रतिबद्धता का पता चलता है। ध्यान रहे 31 दिसंबर 2012 को 'जेन जी' के आखिरी बच्चे का जन्म हुआ था। उसके बाद जन्मे बच्चे 'जेन अल्फा' यानी 2014 में बनीं शिक्षा मंत्री के ऊपर ही 'जेन जी' का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी। उनके ऊपर यह जवाबदेही थी कि 1997 से 2012 के बीच जन्मे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे प्रशिक्षण और नौकरी व रोजगार की व्यवस्था करें। क्या स्मृति ईरानी इस काम के लिए उपयुक्त थीं?

उसी दिन पता चल गया कि इस सरकार को शिक्षा के साथ क्या करना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बौद्धिक जमात से नाराज थे। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते बौद्धिक जमात ने उनको बहुत निशाना बनाया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर जेएनयू और देश के दूसरे शिक्षा केंद्रों में बैठे लोग उनके ऊपर हमला थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको इसका बदला लेना था। उन्होंने देश की बौद्धिक जमात को, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को, महाविद्यालयों के प्राचार्यों को, बड़े शैक्षिक संस्थानों को निदेशकों आदि को अपमानित करना था और इसके लिए ही स्मृति ईरानी के शिक्षा मंत्री बनाया गया। उन्होंने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हालांकि यह परंपरा वही पर समाप्त नहीं हो गई। स्मृति ईरानी के बाद प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया। सबने मिल कर देश के नामी विश्वविद्यालयों में ऐसे कुलपति नियुक्त किए, जिनका शिक्षा और गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं रहा। आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थानों में ऐसे निदेशक नियुक्त किए गए, जिनकी योग्यता 'भाई साहब' लोगों की परिक्रमा से ज्यादा कुछ नहीं थी। रिसर्च संस्थानों में ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई जिनका शोध कार्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल अलग कसौटियों पर लोगों को नियुक्त किया गया। केंद्र से लेकर राज्यों तक में पाठ्यक्रम तैयार करने और नई किताबें लिखने के लिए जो लोग चुने गए उन्हें इस विधा का कोई अंदाजा नहीं था।

व्यंग्य

यूजर्स पर अनावश्यक बोझ

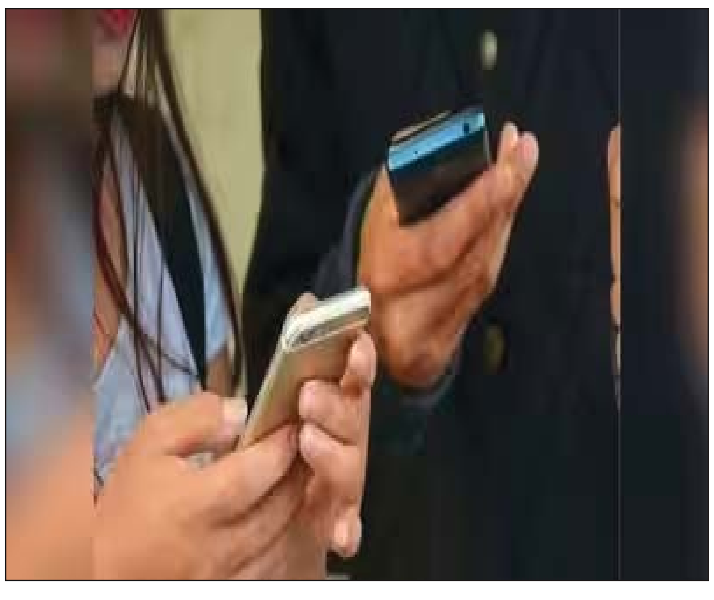

मोदी सरकार उचित ही यूपीआई की सफलता को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती आई है। अब यह समझना कठिन है कि अपनी इस कामयाबी को पलटने का रास्ता वह क्यों तैयार कर रही है?

केंद्र ने संसद से वह विधेयक पारित करवा लिया है, जिसके बाद बैंकों को यूपीआई पेमेंट पर फीस लगाने का अधिकार देने का रास्ता खुल गया है। यह आपत्तिजनक पहल है। नरेंद्र मोदी सरकार उचित ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सफलता को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती आई है। मोदी सरकार रुपे कार्ड की शुरुआत कर स्वदेशी भुगतान की एक और महत्त्वपूर्ण पहल करने में सफल रही थी। अब यह समझना कठिन है कि अपनी बड़ी कामयाबी को पलटने का रास्ता वह क्यों तैयार कर रही है? सरकार ने खुद कहा है कि बड़े लेनदेन कारोबारियों से बैंकों को भुगतान फीस वसूलने का अधिकार दिया जा सकता है।

सरकार का दावा है कि इससे महज पांच प्रतिशत यूजर प्रभावित होंगे। यानी आम भुगतानकर्ताओं पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर, व्यवहार में इसे सुनिश्चित करना शायद संभव नहीं होगा। वेंडर्स यूजर्स पर उन शुल्कों को ट्रांसफर ना करें, इसकी गारंटी करना बेहद कठिन साबित होगा। नतीजतन, फीस का चलन लागू होने के बाद व्यवहार में असल में यह होगा कि लोग नकदी लेनदेन या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की दिशा में लौटेंगे। यह सरकार की घोषित प्राथमिकताओं के खिलाफ होगा। वैसे भी, जब सरकार यह सिस्टम चलाने के लिए हर साल डेढ़ से दो हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी बैंकों को दे रही है, तो फिर बैंकों को फीस लेने की आजादी देने का क्या तर्क हो सकता है?

ऐसे प्रश्नों का सटीक उत्तर मौजूद ना होने के कारण ही इस संदेह को हवा मिली है कि इस फैसले के पीछे अमेरिकी दबाव की भूमिका है। यूपीआई और रुपे कार्ड के चलन में आने से अमेरिकी कंपनियों- मास्टरकार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि के भारत में मौजूद बाजार पर प्रतिकूल असर पड़ा। अब कहा जा रहा है कि उन कंपनियों के हित में भारत पर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का परोक्ष दबाव पड़ा है। मुमकिन है कि ऐसी बातों में कोई दम ना हो। मगर खुद मोदी सरकार ने भारतीय कारोबारियों और यूजर्स पर अनावश्यक बोझ डालने की तैयारी कर ऐसी चर्चाओं की जमीन तैयार की है।

ब्लॉग

महिला सशक्तिकरण पर राहुल गांधी की खोखली बयानबाज़ी बनाम मोदी सरकार का ठोस रिकॉर्ड

ए. शक्तिवेल

पुणे में महिला सशक्तिकरण पर राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी सुनने में आकर्षक लग सकती है, लेकिन यह एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैः क्या महिला सशक्तिकरण को केवल राजनीतिक भाषणों से मापा जाना चाहिए, या फिर उन कानूनों, अवसरों और संस्थाओं से, जो महिलाओं को वास्तव में अधिकार और अवसर प्रदान करते हैं? इस कसौटी पर नरेंद्र मोदी सरकार का रिकॉर्ड व्यापक है, जबकि महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण सुधारों के मामले में कांग्रेस बार-बार सवालों के घेरे में रही है।

महिला सशक्तिकरण के प्रति मोदी सरकार का दृष्टिकोण मूल रूप से अलग रहा है। यह केवल कल्याण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अधिकार, गरिमा, प्रतिनिधित्व, वित्तीय आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और महिला नेतृत्व वाले विकास तक विस्तारित हुआ है। तत्काल तीन तलाक को समाप्त करने से लेकर विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण को संवैधानिक आधार देने तक, सरकार ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस कानून ने तत्काल तीन तलाक को अमान्य घोषित किया और मुस्लिम महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान किया। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को एक मनमानी प्रथा से सुरक्षा देने वाले इस उपाय का स्वागत करने के बजाय कांग्रेस ने विधेयक के पारित होने के दौरान इसका विरोध किया। इसलिए सवाल आज भी प्रासंगिक हैः जब कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, तो उसने मुस्लिम महिलाओं को कानूनी संरक्षण और गरिमा देने वाले कानून का विरोध क्यों किया था? इसी तरह नारी शक्ति वंदन अधिनियम, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून संवैधानिक व्यवस्था के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है। यह स्वतंत्र भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों में से एक है। फिर भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने महिलाओं के आरक्षण के क्रियान्वयन से जुड़ी परिसीमन प्रक्रिया पर आपत्तियां उठाई हैं। यदि कांग्रेस वास्तव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहती है, तो वह उस संवैधानिक व्यवस्था पर अड़चन क्यों पैदा करती है जिसके माध्यम से यह प्रतिनिधित्व वास्तविकता में बदलना है? यह केवल राजनीतिक मतभेद नहीं है। यह कांग्रेस के दृष्टिकोण में एक गहरे विरोधाभास को सामने लाता है। महिलाओं के आरक्षण की बात करना एक बात है, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलने वाली संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना दूसरी। महिलाओं को राजनीतिक दोहरे मापदंड नहीं, वास्तविक प्रतिनिधित्व चाहिए।

कांग्रेस के अपने राज्यों का रिकॉर्ड देखें तो यह विरोधाभास और गहरा हो जाता है। कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है और राज्य मंत्रिपरिषद में एक भी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया है। जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उसे अपने ही शासन और संगठनात्मक फैसलों में भी अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए।

कांग्रेस को अपने संगठन के भीतर महिलाओं के साथ व्यवहार को लेकर भी सवालों के जवाब देने होंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने उन पार्टी कार्यकर्ताओं की बहाली पर आपत्ति जताने के बाद कांग्रेस छोड़ी थी, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार और धमकी दी थी। राधिका खेड़ा ने भी बाद में पार्टी के भीतर उत्पीड़न और अपमान के आरोप सार्वजनिक रूप से उठाने के बाद कांग्रेस छोड़ दी। ये घटनाएं एक सीधा सवाल खड़ा करती हैंः देश को महिलाओं की गरिमा पर भाषण देने से पहले क्या राहुल गाँधी अपने ही राजनीतिक संगठन में महिलाओं की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित कर सकते हैं?

मोदी सरकार का रिकॉर्ड केवल कानूनों तक सीमित नहीं है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 68 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। अप्रैल 2026 तक कुल 57.79 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके थे, जिनकी कुल राशि ?40.07 लाख करोड़ से अधिक थी। इनमें लगभग दो तिहाई ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। यही जमीन पर वास्तविक सशक्तिकरण है। जब किसी महिला को संस्थागत ऋण मिलता है, तो वह केवल सरकारी सहायता प्राप्त नहीं करती। उसे अपना व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने, आय अर्जित करने और औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अवसर मिलता है। मोदी सरकार ने महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में देखने के बजाय उन्हें उद्यमी, रोजगारदाता और आर्थिक निर्णयकर्ता बनाने की दिशा में काम किया है।

यही परिवर्तन स्टार्टअप इंडिया में भी दिखाई देता है। डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग आधे स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया के तहत 75,000 से अधिक महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को समर्थन दिया गया है। संदेश स्पष्ट हैः महिलाएं पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं। वे तेजी से संस्थापक, नवोन्मेषक और कारोबारी नेतृत्वकर्ता बन रही हैं।

ग्रामीण महिलाओं की कहानी भी उतनी ही प्रभावशाली है। लखपति दीदी ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व वाले विकास के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक बन चुकी है। इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कम से कम ?1 लाख की टिकाऊ वार्षिक आय हासिल करने में सक्षम बनाना है। मई 2026 तक, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, 3.07 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। जुलाई 2026 तक सरकार ने बताया कि 3.46 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को लखपति दीदी बनने में सक्षम बनाया गया हैं।

यह एक गहरा सामाजिक परिवर्तन है। जो महिला कभी पूरी तरह घरेलू अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी, वह अब आय अर्जित करने वाली, उद्यमी और निर्णयकर्ता बन रही है। स्वयं सहायता समूहों, बैंक ऋण, कौशल, तकनीक और बाजार तक पहुंच के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है।

नमो ड्रोन दीदी पहल इस सशक्तिकरण को एक कदम और आगे ले जाती है। महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन संचालित करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे आजीविका के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और आधुनिक तकनीक भारत के गांवों तक पहुंच रही है। सरकार ने ?1,261 करोड़ के प्रावधान के साथ चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

वित्तीय समावेशन की कहानी भी महत्वपूर्ण है। जुलाई 2026 तक 32.68 करोड़ जनधन खाते महिलाओं के नाम पर खोले गए हैं, जिससे करोड़ों महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग और सरकारी वित्तीय प्रणालियों तक सीधी पहुंच मिली। स्टैंड-अप इंडिया के तहत दो लाख से अधिक महिला उद्यमियों को नए उद्यम स्थापित करने में सहायता दी गई है। लेकिन महिला सशक्तिकरण की कहानी केवल बैंक खाते, ऋण और उद्यमिता तक सीमित नहीं है। यह महिलाओं के दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, सम्मान और समय से भी जुड़ी है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मई 2026 तक गरीब परिवारों की महिलाओं को 10.57 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इससे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम हुई, घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई और महिलाओं के स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन ने महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया। देश में 12 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। शौचालय केवल स्वच्छता का विषय नहीं है; यह महिलाओं की निजता, सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन ने खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने की दिशा में एक व्यापक सामाजिक बदलाव को जन्म दिया है। जल जीवन मिशन ने भी ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव किया है। अगस्त 2019 में मिशन शुरू होने के समय केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल से जल की सुविधा थी। मार्च 2026 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 15.82 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गई, यानी लगभग 81.71 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा उपलब्ध हो चुकी थी। इसका सबसे बड़ा लाभ उन महिलाओं को मिला है, जिन पर वर्षों से परिवार के लिए दूर-दराज से पानी लाने का बोझ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार, हर ग्रामीण परिवार तक नल से पानी पहुंचने पर महिलाओं के प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे तक बच सकते हैं। इस बचाए गए समय का उपयोग महिलाएं शिक्षा, रोजगार, आय अर्जित करने वाली गतिविधियों और परिवार की देखभाल में कर सकती हैं।

विधायी रिकॉर्ड भी व्यापक है। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने पात्र महिलाओं के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया और क्रेच सुविधाओं तथा घर से काम करने से जुड़े प्रावधान पेश किए। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने यौन अपराधों से संबंधित प्रावधानों को मजबूत किया, जिसमें नाबालिगों से बलात्कार के लिए कड़े दंड शामिल हैं। वेतन संहिता, 2019 ने पारिश्रमिक में लैंगिक समानता के ढांचे को मजबूत किया। सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 का उद्देश्य महिलाओं को शोषण से बचाना है, जबकि चिकित्सकीय गर्भसमापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने निर्धारित परिस्थितियों में सुरक्षित और कानूनी गर्भसमापन सेवाओं तक पहुंच का विस्तार किया। बड़ी तस्वीर भी स्पष्ट है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2017-18 और 2023-24 के बीच महिलाओं के रोजगार में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है, जबकि पिछले एक दशक में जेंडर बजट में 429 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार इस बदलाव को महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ने के रूप में बताती है।

हाथरस पीड़ित परिवार को नोएडा या गाजियाबाद में बसाने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दी 3 महीने की मोहलत

आर्यावर्त संवाददाता

हाथरस। हाथरस की चर्चित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना के पीड़ित परिवार के पुनर्वास को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार को सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल में बसाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। इसके लिए नोएडा या गाजियाबाद जैसे शहरों में पुनर्वास पर विचार करने को कहा गया है। सरकार को आदेश के अनुपालन के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।

हाथरस कांड के बाद पीड़ित परिवार की सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर हाईकोर्ट लगातार निगरानी कर रहा है। हाईकोर्ट ने पहले भी परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुरूप सरकारी या सरकारी उपक्रम में नौकरी देने और परिवार को

हाथरस से बाहर बसाने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया था। लेकिन लंबे समय बाद भी पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई।

अड़ियल रवैया नहीं चलेगा-कोर्ट

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठने सरकार के रवैये पर सख्त टिप्पणी करते हुए साफ किया कि कोर्ट के आदेशों का अनुपालन टालने वाला रवैया स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने परिवार की सुरक्षा और सामान्य जीवन जीने के अधिकार को गंभीरता से लेते हुए सरकार को पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। कोर्ट के सामने यह भी बताया गया कि परिवार के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से रोजमर्रा के कामों में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीआरपीएफ जवान उनकी सुरक्षा में साथ चलते हैं, जिससे बाजार जाने, डॉक्टर को दिखाने और बच्चों को स्कूल ले जाने तक की गतिविधियां सामान्य नहीं रह गई हैं।

2022 में ही दिया था बाहर बसाने का आदेश

हाथरस कांड के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुलाई 2022 में परिवार के पुनर्वास को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। कोर्ट ने सरकार से परिवार को हाथरस से बाहर प्रदेश में किसी उपयुक्त स्थान पर बसाने और परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार देने पर विचार करने को कहा था। इसके बावजूद जुलाई 2024 में भी हाईकोर्ट को बताया गया था कि परिवार का दूसरे स्थान पर पुनर्वास नहीं हो सका है। कोर्ट ने तब भी अपने पुराने आदेश के अनुपालन की समीक्षा करने की बात कही थी।

सुरक्षा के साये में गुजर रही जिंदगी

हाथरस की घटना के बाद परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी थी। परिवार के घर के आसपास पुलिस और पीएसी की तैनाती के साथ निगरानी के अन्य इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन कोर्ट के सामने परिवार की ओर से लगातार यह चिंता सामने आती रही है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद वे अपने पुराने माहौल में सहज और सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में अब हाईकोर्ट ने पुनर्वास के मुद्दे को फिर से गंभीरता से उठाया है।

सरकार के सामने तीन महीने में समाधान की चुनौती

हाईकोर्ट के ताजा रुख के बाद अब राज्य सरकार के सामने परिवार के पुनर्वास को लेकर स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने की चुनौती है। नोएडा या गाजियाबाद जैसे शहर में परिवार को बसाने का विकल्प इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे परिवार को हाथरस से बाहर सुरक्षित माहौल मिल सकता है और शिक्षा, रोजगार तथा अन्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच भी संभव होगी।

क्या है हाथरस घटना

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 14 सितंबर, 2020 को एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की कथित घटना सामने आई थी, घटना के करीब दो सप्ताह बाद दिल्ली के एक अस्पताल में युवती की मौत हो गई थी। मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अपने बयान में पीड़िता ने चार आरोपियों पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने परिवार की सहमति के बिना रात में पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया था। हालांकि, पुलिस ने इस दावे को गलत बताया था।

अधिकारों के लिए आगे आ रही महिलायें

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। सिपाह स्थित राजमंडल में डीडीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शाखा पर समान शिक्षा अधिकार एवं महिला-पुरुष समानता को लेकर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं पुरुषों के लिए समान शिक्षा के अधिकार, बदलते सामाजिक परिवेश तथा आधुनिक भारत में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि आज की युवा पीढ़ी महिला और पुरुष के बीच भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। समाज में मौजूद विभिन्न कुरीतियों और रूढ़ियों से संघर्ष करते हुए आधुनिक युग की महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में नए इतिहास रच रही हैं। वकताओं ने कहा कि वास्तविक शिक्षा वह है, जो व्यक्ति के

संस्कार, व्यक्तित्व और ज्ञान को मजबूत बनाए तथा उसे समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता प्रदान करे। शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने अधिकारों को समझता है, बल्कि वंचित और जरूरतमंद लोगों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाने में सक्षम होता है। कार्यक्रम में डीडीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के विभिन्न सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें दिलरूबा परवीन, महरूबा परवीन, रूबी यादव, बबिता निषाद, यामिश, नेहा, शुग्रा सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।

जश्ने यौमुन्न नबी का ऐतिहासिक जुलूस निकला

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। मुस्लिम जगत गुधार को इस्लाम के आखरी पैगम्बर का जन्मोत्सव मना रहा है। शहर में भी पिछले 126 वर्षों से एक जश्ने यौमुन्न नबी मनाया जा रहा है जिसमें लोग अपनी अपनी खुशी का इजहार करते हैं । विभिन्न अंजुमन नात पढ़ती है और विभिन्न अखाड़े अपने अपने करतब दिखाते चलते है । जुलूस अपनी पुरानी रिवायत के अनुसार शाम मुख्य अतिथि अंसार अहमद ,, और सदर अध्यक्ष कमेटी ओबैदा शिराजी खान के द्वारा हरी झंडी दिखा कर रवाना हुआ। जो पूरी रात विभिन्न अखाड़ों के करतब और अंजुमने अपनी नात पढ़ते हुए ओलन्दगंज से शाही पुल ,चहारसू होता हुआ किदवई पार्क कोतवाली चौराहा के कंट्रोल रूम के सामने से होता हुआ अल्फिस्टीनगंज से शाही अटाला मस्जिद पहुंच कर एक जलसे में तब्दील हो गया।इस दरमियान

विभिन्न संस्थानों ने इंस्टॉल लगा कर पानी ,नाश्ता और भोजन की व्यवस्था की ,वही विभिन्न अलग अलग स्टेज से लोग अंजुमनों और अखाड़ों को पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई करते रहे ।जलसा रात भर बच्चों ,औरतों और सभी समुदायों के लोगों से गुलजार रहा।कौमी एकजहती राष्ट्रीय एकता प्रोग्राम की अध्यक्षता मौलाना अनवार कासमी ने की कार्यक्रम की शुरुआत कलामे इलाही से यासिर एहसान ने किया । मुख्य वक्ता ने बताया कि हजरत मोहम्मद साहब के आने से पहले समाज में बहुत गिरावट आ चुकी थी लोग लड़की पैदा होते ही उसे जिंदा दफन कर देते थे।शराब ,और विभिन्न आपसी रंजिशो के युद्धों से समाज त्रस्त था ऐसे में हजरत पैगम्बर मक्का शहर में पैदा हुए और पूरी दुनिया में बुराई को दूर करने के लिए एक मिशन चलाया जिसको उनके बाद उनके अनुयायियों ने जारी रखा।

सांसद प्रतिनिधि सहित चार को आजीवन कारावास

जौनपुर। पर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने लाइन बाजार थाना क्षेत्र में 22 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर मोहल्ला निवासी पवन मौर्य ने 16 अगस्त 2004 को मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसका कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता रहे रामसेवक मौर्य से जमीन का विवाद चल रहा था जिसमें आज कमिश्नर मौका मोआइना के लिए आने वाले थे। सुबह 8:30 बजे रामसेवक मौर्य, उनके चारों पुत्र अश्वनी कुमार मौर्य, आशीष मौर्य, मनोज कुमार मौर्य, पवन मौर्य और पड़ोसी राजेश उर्फ छोटू विवादित जमीन पर बांस बल्ली गाड़कर कब्जा करने लगे। वादी के मना करने पर विवाद हो गया और जिसमें आशीष मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रामसेवक मौर्य के घर से हत्या में प्रयुक्त बंदूक बरामद हुई थी।

बंद मकान में मिला महिला का सड़ा-गला शव... पति फरार, बेटे ने खोली बाप की पुरानी क्राइम हिस्ट्री

आर्यावर्त संवाददाता

बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के मंडावली थाना क्षेत्र अंतर्गत नयागांव उर्फ मिर्जापुर सैद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बंद मकान के अंदर कमरे में चारपाई पर महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। शव कई दिन पुराना होने के कारण बुरी तरह सड़-गल चुका था और उसमें कीड़े पड़ चुके थे, जिससे पूरे इलाके में दुर्गंध फैल गई।

मृतका की पहचान शहनाज परवीन के रूप में हुई है। वह अपने पति अहमद हसन और बच्चों के साथ उत्तराखंड के श्रीनगर में रहती थी। जमीन से जुड़े किसी काम के सिलसिले में यह दंपत्ति बीते मंगलवार को ही अपने पैतृक गांव आया था। शहनाज के छह बच्चे हैं और उनके तीनों बेटे श्रीनगर में ही काम करते हैं।

बुधवार शाम शहनाज की अपने बड़े बेटे आसिफ से फोन पर आखिरी बार बातचीत हुई थी। इसके बाद जब आसिफ श्रीनगर से अपने गांव पहुंचा, तो मकान के मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लटका मिला। आसिफ के पास घर की दूसरी चाबी थी। जैसे ही उसने ताला खोलकर कमरे में प्रवेश किया, अंदर का दृश्य देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। चारपाई पर उसकी मां का अर्धनग्न और सड़ा-गला शव पड़ा हुआ था।

'पिता जुआरी और शक्की, जुए में बेचा था घर'

घटना के तुरंत बाद आसिफ ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी और अपने पिता अहमद हसन पर मां की हत्या का सीधा आरोप लगाया। आसिफ ने बताया कि उसका पिता बेहद शक्की स्वभाव का था और अक्सर मां के साथ मारपीट करता था। इससे पहले भी वह कई बार मां को जान से मारने की कोशिश कर चुका था। बेटे का आरोप है कि उसका पिता जुए और अय्याशी का आदी था और जुए के चक्कर में उसने अपना पुराना मकान भी बेच दिया था। वारदात के बाद से ही आरोपी पिता का मोबाइल बंद है और वह मौके से फरार है।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही मंडावली थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव की गंभीर स्थिति को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। थानाध्यक्ष के अनुसार मौत के सही कारणों और समय की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हो सकेगी। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और फरार पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं।

सर्पदंश से बालक की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। बरसठी थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में मंगलवार रात सर्पदंश से 10 वर्षीय अंश पटेल की मौत हो गई। वह माता-पिता का इकलौता बेटा था। रक्षाबंधन से ठीक दो दिन पहले हुई इस दर्दनाक घटना से परिवार में मातम छा गया। इकलौते भाई की मौत से 13 वर्षीय बहन खुशी का भी रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार, रात करीब आठ बजे अंश घर के बरामदे में खाना खाने के बाद पानी लेने के लिए बाल्टी के पास जा रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली चली गई और बरामदे में अंधेरा हो गया। बाल्टी के पास मौजूद सांप ने अंश को डस लिया। सर्पदंश की जानकारी मिलते ही परिजन अंश को तत्काल मड़ियाहूं लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जौनपुर के एक निजी अस्पताल

रेफर कर दिया। वहां से अंश को बीएचयू भेजा गया, जहां उपचार के दौरान रात में उसकी मौत हो गई। अंश भन्नौर स्थित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा चार का छात्र था। वह राजकुमार पटेल और सुषमा देवी का इकलौता पुत्र था। उसकी 13 वर्षीय बहन खुशी है। रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना के बाद गांव में भी शोक की लहर है।

अखिलेश यादव के बयान पर बागपत में सियासी बवाल : सपा प्रमुख के खिलाफ रातोंरात लगे पोस्टर, कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा

आर्यावर्त संवाददाता

बागपत। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रालोद प्रमुख एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी पर दिए गए चवन्नी से रुपये बनाने के बयान के बाद विरोधी उन्हें घेरने में जुट गए हैं। उनके खिलाफ जनपद में पोस्टर लगाए गए। उन पर गंभीर आरोप लगाए गए है। वहीं इससे सपाई नाराज है।

उन्होंने सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा करते हुए खुद पोस्टर हटाए। चेतावनी दी कि पुलिस ने एक घंटे में पोस्टर लगाने वालों का पता नहीं लगाया गया तो हाईवे जाम किया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

विरोध में राष्ट्वंदना चौक पर प्रदर्शन करते हुए सपा कार्यकर्ता एसपी ऑफिस पहुंच गए। एसपी ऑफिस में घुसने को लेकर पुलिसकर्मियों व सपाइयों में धक्का-मुक्की हुई। सपा प्रमुख अखिलेश

यादव के इस बयान के बाद राजनीति गरमाई हुई है। इस पर केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने भी पलटवार किया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी टिप्पणी की थी। वहीं सोशल मीडिया पर पार्टी समर्थकों ने खूब कमेंट्स किए। यहां तक ही यह मामला नहीं रुका। मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ बागपत जनपद में विभिन्न स्थानों पर पोस्ट चस्पा कर दिए गए।

उन पर जातिवाद आदि आरोप लगाए गए। इसका पता चलते ही सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। उन्होंने गली, मोहल्लों में जाकर पोस्टरों को हटाया। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान का कहना है कि यह निंदनीय कार्य है।

चेतावनी दी कि एक घंटे में पुलिस-प्रशासन ने पोस्टर लगाने वाले का पता नहीं किया तो राष्ट्र वंदना चौक पर पहुंचकर जाम लगा दिया जाएगा। जनपद में पार्टी कमजोर नहीं है। उन्होंने ऐसा करने वालों को सामने आने की खुली चुनौती दे दी है। वहीं पुलिस व खुफिया तंत्र हर गतिविधियों पर नजर लगाए है। उधर एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

बाजारों में सजी राखियों की दुकानें

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। रक्षाबंधन पर्व को लेकर जिले भर में बाजारों में राखियों की दुकानें सज गई हैं। बाजार में तरह-तरह की रंग-बिरंगी और आकर्षक राखियां बहनों को लुभा रही हैं। रक्षाबंधन नजदीक आते ही राखी खरीदने के लिए बाजार में महिलाओं और युवतियों की भीड़ बढ़ने लगी है। बहनों ने भाइयों की कलाई सजाने के लिए अपनी पसंद की राखियां खरीदीं। दुकानों पर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों के साथ ही मोतियों, रुद्राक्ष और डिजाइनर राखियों की भी खूब मांग रही। दुकानों में फैंसी राखियों की चमक देखते ही बन रही है। राखी खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में दुकानदारों ने भी तरह-तरह की राखियों का स्टॉक जुटा लिया है। इस बार बाजार में एक रुपये से लेकर 500 रुपये तक की राखियां

उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर और आकर्षक डिजाइन वाली राखियां पसंद की जा रही हैं। युवतियों और महिलाओं में फैंसी, मोती, स्टोन व डिजाइनर राखियों की मांग अधिक है। पारंपरिक लाल, पीली, हरी, गुलाबी व नारंगी रंग के धागों वाली राखियां भी खूब बिक रही हैं। राखियों के साथ चॉकलेट, गिफ्ट पैक व भाई के लिए उपहारों की दुकानों पर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। फुटकर दुकानदार थोक बाजार से राखियों की खरीदारी कर अपनी दुकानों को आकर्षक ढंग से सजा रहे हैं।

हर 100 में से 7 बुजुर्ग परेशान, अब इनके लिए यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों की संख्या भले ही कुल आबादी का एक छोटा हिस्सा हो, लेकिन उनकी समस्याएं लगातार बड़ी होती जा रही हैं। CSDS के मुताबिक, यूपी की करीब 8 फीसदी आबादी बुजुर्गों की है। ऐसे में राज्य में लाखों वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं, जिनके सामने उम्र बढ़ने के साथ आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, अकेलेपन और परिवार से जुड़ी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट ने बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता बढ़ाई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे में शामिल करीब हर तीन में से एक बुजुर्ग के पास अपनी कोई आय नहीं थी। यह सर्वे 10 राज्यों में 5,000 से ज्यादा बुजुर्गों और करीब 1,300 देखभाल करने वालों के बीच किया गया था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 40 फीसदी बुजुर्ग अशिक्षित थे और 7 फीसदी ने खुद को किसी न किसी तरह के दुर्व्यवहार का शिकार

बताया। यह स्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि बुजुर्गों की जरूरत केवल पेंशन या आर्थिक मदद तक सीमित नहीं होती।

सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का इस्तेमाल

उम्र बढ़ने के साथ उन्हें इलाज, दवाइयों, सुरक्षित रहने की जगह, परिवार का सहारा और कई बार कानूनी मदद की भी जरूरत पड़ती है। हेल्पएज इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया कि पिछले एक साल में 79 फीसदी बुजुर्ग सरकारी अस्पताल, क्लीनिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए। 80 साल से ज्यादा उम्र के जिन बुजुर्गों ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का इस्तेमाल किया, उनमें करीब आधे के पास अपनी कोई व्यक्तिगत आय नहीं थी।

बुढ़ापे में सबसे बड़ी चिंता आर्थिक सुरक्षा की होती है। नौकरी या नियमित कमाई खत्म होने के बाद बुजुर्गों की निर्भरता परिवार या सरकारी योजनाओं पर बढ़ जाती है। सर्वे में एक तिहाई बुजुर्गों ने पिछले एक साल में कोई आय नहीं होने की बात कही। महिलाओं की स्थिति और

यूपी की करीब 8 फीसदी आबादी बुजुर्गों की है।

सर्वे में हर तीन में से एक बुजुर्ग के पास आय का स्रेत नहीं था।

करीब 40 फीसदी बुजुर्ग अशिक्षित पाए गए।

7 फीसदी बुजुर्गों ने दुर्व्यवहार का अनुभव बताया।

79 फीसदी बुजुर्ग पिछले एक साल में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गए।

आर्थिक रूप से कमजोर क्यों हैं बुजुर्ग?

कमजोर दिखाई दी। रिपोर्ट के अनुसार, 38 फीसदी बुजुर्ग महिलाओं के पास आय का स्रोत नहीं था, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 27 फीसदी था।

परिवार से जुड़ी परेशानी भी बड़ी चिंता

इसका असर केवल रोजमर्रा के खर्च पर नहीं पड़ता। पैसे की कमी होने पर दवाइयों, इलाज और दूसरी जरूरी चीजों के लिए भी बुजुर्गों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। यही वजह है कि बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा और नियमित आय का इंतजाम बेहद जरूरी माना जाता है। बुजुर्गों के लिए आर्थिक समस्या के साथ परिवार का व्यवहार भी बड़ा मुद्दा है। सर्वे में 7 फीसदी बुजुर्गों ने दुर्व्यवहार की बात कही। जिन मामलों में दुर्व्यवहार की जानकारी सामने आई, उनमें बेटे 42 फीसदी मामलों में और बहुएं 28 फीसदी मामलों में मुख्य आरोपी बताए गए।

योगी सरकार की नई पहल क्या है?

बुजुर्गों के अधिकार और सम्मान को लेकर यूपी सरकार नई व्यवस्था पर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार बुजुर्गों की समस्याओं में मदद के लिए टोल-फ्री नंबर शुरू करने और मौजूदा नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसका मकसद वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों को सुनना और उनके अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करना है। हालांकि, बुजुर्गों के लिए केंद्र की Elderline 14567 पहले से मौजूद है। यह टोल-फ्री हेल्पलाइन स्वास्थ्य, पेंशन, कानूनी मदद, सरकारी योजनाओं, भरण-पोषण और दुर्व्यवहार जैसी समस्याओं में जानकारी और सहायता देती है। यूपी में भी यह सेवा पहले से संचालित है। इसलिए यूपी सरकार की प्रस्तावित नई व्यवस्था और मौजूदा Elderline के बीच क्या अंतर होगा, यह उसके आधिकारिक विवरण के बाद ही साफ होगा।

शिकायत पर 30 दिन में सुनवाई

सर्वे में घर पर रहने वाले बुजुर्गों की हिस्सेदारी 7।7 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसके अलावा, 56 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की कुल हिस्सेदारी 19।2 प्रतिशत है।वित्त मंत्री ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को इस व्यवस्था का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए बेदखली की प्रक्रिया को स्पष्ट और समयबद्ध बनाया गया है। नए प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की जा सकेगी और शिकायतों की सुनवाई 30 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट को इन मामलों की मासिक रिपोर्ट भी सरकार को देनी होगी। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, उनके अधिकारों की सुरक्षा और अत्याचार या दुर्व्यवहार से बचाव सुनिश्चित करना है, साथ ही परिवार के सदस्यों को अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और सम्मान के प्रति जिम्मेदार बनाना भी है।

स्वास्थ्य भी बड़ी चुनौती

बुजुर्गों की बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य खर्च भी बढ़ता है। हेल्पएज इंडिया के सर्वे में 79 फीसदी बुजुर्गों के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाने की बात सामने आई। वहीं सिर्फ 31 फीसदी बुजुर्गों ने Ayushman Bharat/PM-JAY के तहत हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होने की जानकारी दी। केवल 3 फीसदी के पास कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस था। रिपोर्ट के मुताबिक, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होने की प्रमुख वजहों में जानकारी की कमी और इसे वहन करने में परेशानी शामिल थी। इसका मतलब है कि बुजुर्गों के लिए सिर्फ अस्पताल उपलब्ध कराना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने में मदद भी जरूरी है।

H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच किसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? डॉक्टर ने बताया

भारत में एच1एन1 इंफ्लुएंजा यानी स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े हुए हैं। किन लोगों पर वायरस का खतरा ज्यादा है ये भी जान लेना जरूरी है

पिछले कुछ दिनों से H1N1 और फ्लू के मामले फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों और ओपीडी में भी बुखार, खांसी, गले में दर्द और शरीर टूटने की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि लोगों में थोड़ी चिंता भी हो। लेकिन सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। H1N1 कोई नया वायरस नहीं है। यह इंफ्लूएंजा ए का ही एक प्रकार है और अब सीजनल फ्लू का हिस्सा बन चुका है। ज्यादातर लोगों में यह बीमारी कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। इसलिए हर बुखार या हर H1N1 केस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।

लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। हर मरीज के लिए इसका खतरा बराबर नहीं होता। एक हेल्दी 25 साल के युवक और 70 साल के ऐसे व्यक्ति, जिसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और सीओपीडी भी है, दोनों को एक ही इंफ्लुएंजा हो सकता है। लेकिन दोनों में खतरे बिल्कुल अलग है। मेरे हिसाब से अभी लोगों को यही बात सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है।

बुजुर्गों में थोड़ी ज्यादा सावधानी जरूरी

डॉक्टर सुचिन बजाज (एमबीबीएस, एमडी, एफआईसीबी, एफआरएसए, एफआईएसीएम) का कहना है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में इंफ्लुएंजा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खासकर अगर साथ में डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी की बीमारी, अस्थमा या सीओपीडी जैसी कोई बीमारी पहले से हो। बुजुर्ग मरीजों में कई बार बहुत तेज बुखार भी नहीं आता। परिवार को लगता है कि केवल कमजोरी है या उम्र की वजह से मरीज सुस्त है। लेकिन अगर अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगे, सांस फूलने लगे, खाना-पीना कम हो जाए या मरीज कंफ्यूज लगे तो डॉक्टर को दिखाने में देर नहीं करनी चाहिए।

छोटे बच्चों में भी नजर बनाए रखें

पांच साल से कम उम्र के बच्चों, खासकर दो साल से छोटे बच्चों में फ्लू कभी-कभी जल्दी बिगड़ सकता है। बच्चे को बुखार और खांसी है लेकिन वह खेल रहा है, पानी पी रहा है और सामान्य तरीके से सांस ले रहा है तो आम तौर पर बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बच्चा बहुत सुस्त हो जाए, दूध या पानी लेना बंद कर दे, बार-बार उल्टी हो या सांस बहुत तेज चलने लगे तो इंतजार नहीं करना चाहिए। माता-पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थर्मामीडर की रीडिंग से ज्यादा बच्चे का बिहेवियर और ब्रेथिंग है।

पहले से बीमार मरीजों को खास ध्यान रखना चाहिए

सबसे ज्यादा चिंता उन मरीजों को लेकर होती है जिन्हें पहले से कोई क्रोनिक बीमारी है। डायबिटीज के मरीज में इंफेक्शन के दौरान शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। अस्थमा या सीपीओडी के मरीज की सांस की समस्या बढ़ सकती है। हार्ट डिजीज वाले मरीजों में इंफ्लुएंजा शरीर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल सकता है। किडनी, लिवर डिजीज या कमजोर इम्यूनिटीवाले मरीजों में भी खतरा ज्यादा रहता है।

कैंसर ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी ले रहे मरीज और लंबे समय से स्ट्रिरॉइड्स या इम्यूनिटी कम करने वाली दवाएं ले रहे लोग भी हाई-रिस्क कैटेगिरी में आते हैं। ऐसे मरीजों को मेरी सलाह रहती है कि बुखार और फ्लू जैसे लक्षण होने पर तीन-चार दिन घर पर यह सोचकर इंतजार न करें कि अपने आप ठीक हो जाएगा। जल्दी अपने डॉक्टर से बात करें।

गर्भवती महिलाएं भी फ्लू को न लें हल्के में

प्रेगनेंसी में शरीर और इम्यूनिटी में कई बदलाव होते हैं, इसलिए इंफ्लुएंजा से कॉम्पलिकेशन्स का रिस्क नॉर्मल से अधिक हो सकता है। गर्भवती महिला को बुखार, खांसी, शरीर दर्द या सांस से संबंधित लक्षण हों तो सेल्फ मेडिकेशन self-medication करने की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।

कब अस्पताल जाने की जरूरत है?

हर H1N1 मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। अधिकांश मरीज घर पर आराम, फ्लूइड्स और सिमप्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ वॉर्निंग साइन्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर सांस लेने में तकलीफ होने लगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही हो, सीने में दर्द हो, मरीज बहुत सुस्त या कंफ्यूज हो, पानी नहीं पी पा रहा हो या ठीक होने के बाद अचानक दोबारा तेज बुखार और खांसी शुरू हो जाए तो medical attention जल्दी लेनी चाहिए। और अगर मरीज पहले से हाई रिस्क कैटेगिरी में है तो इन लक्षणों के आने का इंतजार भी नहीं करना चाहिए।

खुद से एंटीबायोटिक शुरू करना सही नहीं

यह भी हम बहुत देखते हैं कि दो दिन बुखार और खांसी हुई और एंटीबायोटिक शुरू कर दिया गया। एच1एन1 वायरल इंफेक्शन है। एंटीबायोटिक वायरस पर काम नहीं करता। एंटीबायोटिक की जरूरत तब हो सकती है जब साथ में बैक्टीरियल इंफेक्शन हो और इसका फैसला डॉक्टर को करने देना चाहिए। कुछ हाई रिस्क मरीजों में एंटीवायरल मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है और इन्हें बीमारी की शुरुआत में देने का ज्यादा फायदा होता है।

जेन-ज़ी को क्यों हो रही है ज्यादा बाल झड़ने की समस्या? जानिए कुछ संभावित कारण

बालों का झड़ना एक आम समस्या है, जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, हाल के अध्ययन बताते हैं कि जनरेशन (जेन-ज़ी) यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों में बालों का झड़ना तेजी से बढ़ रहा है। यह समस्या खासकर महिलाओं में अधिक देखी जा रही है। आइए जानते हैं कि क्यों बालों का झड़ना जेन-ज़ी के लोगों में अधिक देखा जा रहा है।

तनाव और मानसिक स्वास्थ्य

जेन-ज़ी के लोग अक्सर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तनाव, चिंता और अवसाद जैसे मुद्दे उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं।

इन समस्याओं का असर न केवल मानसिक, बल्कि शारीरिक सेहत पर भी पड़ता है। बालों का झड़ना भी इसका एक लक्षण हो सकता है।

जब व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है तो उसका शरीर भी प्रभावित होता है, जिससे बाल तेजी से झड़ने लगते हैं।

सोशल मीडिया का प्रभाव

सोशल मीडिया ने जेन-ज़ी पर गहरा असर डाला है। वे अपने जीवन की हर छोटी-बड़ी घटना को सोशल मीडिया पर साझा करते हैं और दूसरों की तुलना करते हैं।

इससे उन्हें आत्म-सम्मान की कमी और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का असर उनके बालों पर पड़ता है, जिससे बाल तेजी से झड़ने लगते हैं।

साथ ही सोशल मीडिया पर सुझाए उत्पाद चुनना भी एक कारण है।

गलत खान-पान और पोषण की कमी

आजकल के लोग फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन ज्यादा करते हैं, जो पोषण से भरपूर नहीं होते और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। सही पोषण न मिलने से बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं।

सही खान-पान से बालों की सेहत बेहतर हो सकती है। इसके लिए हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन युक्त आहार और पानी का सेवन बढ़ाना जरूरी है।

साथ ही विटामिन और मिनरल की कमी को दूर करने पर ध्यान दें।

हेयर स्टाइलिंग उपकरणों का अत्यधिक उपयोग

हेयर स्टाइलिंग उपकरण, जैसे स्ट्रेटनर और कर्लर आदि का अत्यधिक उपयोग भी बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। इन उपकरणों से बालों को सीधा या घुमा कर स्टाइल किया जाता है, लेकिन इनकी गर्मी से बाल कमजोर हो जाते हैं।

इसलिए, इनका उपयोग कम से कम करें और प्राकृतिक तरीकों से हेयर स्टाइलिंग करें। इसके अलावा हेयर स्टाइलिंग के लिए प्राकृतिक उपायों का उपयोग करें, ताकि बाल स्वस्थ रहें और झड़ने की संभावना कम हो।

केमिकल युक्त हेयर उत्पाद का इस्तेमाल

बाजार में कई तरह के हेयर उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें रासायनिक तत्व होते हैं, जो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। जेन-ज़ी के लोग अक्सर इन उत्पादों का इस्तेमाल करते समय इनकी गुणवत्ता या सामग्री पर ध्यान नहीं देते, जिससे उनके बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं।

इन कारणों से साफ है कि बालों का झड़ना जेन-ज़ी के लोगों में एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिससे निजात पाने के लिए उन्हें इन समस्याओं पर ध्यान देना होगा।

सनस्क्रीन स्टिक का इस्तेमाल करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा फायदा

सनस्क्रीन स्टिक एक नए प्रकार की सनस्क्रीन है, जिससे आप अपनी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचा सकते हैं। यह छोटी स्टिक के आकार की होती है और इसे आसानी से त्वचा पर लगाया जा सकता है। हालांकि, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। आइए जानते हैं कि सनस्क्रीन स्टिक का इस्तेमाल करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

त्वचा को साफ करें

सनस्क्रीन स्टिक का उपयोग करने से पहले त्वचा को अच्छे से साफ कर लें। इसके लिए हल्के फेसवॉश का उपयोग करें, जिससे आपकी त्वचा से गंदगी और तेल निकल जाए।

इसके बाद टॉवल से हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं। साफ त्वचा पर ही सनस्क्रीन स्टिक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे यह बेहतर तरीके से काम करती है और आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचा सकती है।

हर इस्तेमाल से पहले सनस्क्रीन स्टिक को भी एक बार पोंछ लें।

सही मात्रा में लगाएं

सनस्क्रीन स्टिक लगाते समय सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर एक-2 बार पूरे चेहरे पर इसे लगाना पर्याप्त होता है।

इसे हल्के हाथों से घुमाते हुए अपने चेहरे पर लगाएं, ताकि हर जगह अच्छी तरह से कवर हो सके। ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में लगाने से त्वचा चिपचिपी हो सकती है और इसका असर भी कम हो सकता है।

इसलिए, हमेशा संतुलित मात्रा में ही सनस्क्रीन स्टिक का उपयोग करें।

समय-समय पर दोहराएं

सूरज की किरणें लगातार आपकी त्वचा पर असर डालती रहती हैं, इसलिए हर 2 घंटे बाद सनस्क्रीन स्टिक को दोहराना जरूरी होता है।

खासकर अगर आप बाहर लंबे समय तक रह रहे हों या पसीना आ रहा हो तो इसे जरूर दोहराएं।

इससे आपकी त्वचा हर समय सुरक्षित रहेगी और आपको सनबर्न जैसी समस्याओं से बचाव मिलेगा।

इस तरह सही तरीके से सनस्क्रीन स्टिक का उपयोग करके आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं।

गर्दन और कानों को न भूलें

अक्सर लोग केवल चेहरे तक ही सीमित रहते हैं और गर्दन और कानों को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, ये हिस्से भी धूप के संपर्क में आते हैं और जलन या काले धब्बों का शिकार बन सकते हैं।

इसलिए, जब भी आप सनस्क्रीन स्टिक लगाएं तो अपनी गर्दन और कानों पर भी ध्यान दें।

इन हिस्सों पर भी समान रूप से सनस्क्रीन स्टिक लगाएं, ताकि ये सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की समस्या से बच सकें।

मेकअप के साथ कैसे उपयोग करें?

अगर आप मेकअप करती हैं तो उसके ऊपर भी सनस्क्रीन स्टिक लगाना आसान होता है।

इसके लिए पहले अपनी त्वचा की देखभाल पूरी करें, फिर हल्का मेकअप करें और अंत में हल्का-सा टचअप करने के बाद सनस्क्रीन स्टिक लगाएं।

इससे आपका मेकअप भी खराब नहीं होगा और आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी। इस तरह सही तरीके से सनस्क्रीन स्टिक का उपयोग करके आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं।

ईपीएफओ और आईटीआर डेटा के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को दिए ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों द्वारा आम लोगों के संवेदनशील ईपीएफओ व आयकर डेटा तक पहुंच पर चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को विशेषज्ञों की मदद से ठोस सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं।

आज के डिजिटल दौर में आपका डेटा ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन अगर महज एक पैन नंबर या यूएएन (UAN) के जरिए आपकी नौकरी व कमाई की पूरी कुंडली किसी निजी कंपनी तक पहुंच जाए, तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अहम मुद्दे पर संज्ञान लिया है। अदालत ने निजी कंपनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) तथा आयकर रिटर्न (ITR) जैसे संवेदनशील डेटा तक पहुंच पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस डेटा के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पुख्ता सुरक्षा उपाय तैयार करे।

खतरे में आपकी निजी जानकारी

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी मोहना की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे की गंभीरता को समझा। आज के समय में ऐसा व्यावसायिक प्रौद्योगिकी तंत्र पनप रहा है जो आसानी से पीएफ व आयकर रिकॉर्ड में मौजूद संवेदनशील निजी जानकारी को निकाल लेता है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए किसी निजी सिस्टम को सिर्फ पैन या यूएएन देता है, तो उस सिस्टम को रोजगार से जुड़ी पूरी जानकारी बिना किसी अड़चन के मिल जाती है।

सिस्टम की बड़ी खामियां

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये है कि डेटा निकालते वक्त न तो कोई ओटीपी (OTP) आता है, न ही यूजर से कोई स्पष्ट सहमति ली जाती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि उसकी जानकारी कब व किसने देख ली। हालांकि, याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि ये मामला सरकारी एजेंसियों द्वारा डेटा लीक का नहीं है। बल्कि ये अलग-अलग कानूनों के तहत सरकारी अधिकारियों को दी गई निजी जानकारी की असुरक्षित स्थिति का मामला है। निजी कंपनियां बिना किसी कड़े सुरक्षा उपाय के इस डेटा तक आसानी से पहुंच बना रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

याचिकाकर्ता पीयूष शर्मा की ओर से दाखिल इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि ये मुद्दा मुख्य रूप से सरकार की नीति के दायरे में आता है। लेकिन कोर्ट ने इस बात को माना कि सरकारी अधिकारियों के पास मौजूद आम जनता के निजी डेटा तक प्राइवेट कंपनियों की पहुंच चिंता का विषय है। इस डेटा का व्यावसायिक इस्तेमाल किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता।

SC ने सरकार को दिए निर्देश

इन सभी दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को क्षेत्र के जानकारों तथा विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए। उनकी सलाह से एक ऐसा असरदार तरीका विकसित किया जाना चाहिए जिससे निजी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संभावित दुरुपयोग को पूरी तरह से रोका जा सके। ईपीएफओ व आयकर आंकड़ों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के बावजूद, जो ये नया पैटर्न उभर रहा है, वो बेहद खतरनाक है। अब इस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पाले में है।

आशीर्वाद आटा पर '100%' लिखने के विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आईटीसी को मिली बड़ी राहत!

दिल्ली हाईकोर्ट ने एफएमसीजी कंपनी आईटीसी (आईटीसी) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने FSSAI से कहा है कि वो आशीर्वाद आटा के '100% शुद्ध' दावे को लेकर कंपनी का लाइसेंस रद्द करने जैसा कोई भी कड़ा फैसला न ले।

देश की बड़ी एफएमसीजी (FMCG) कंपनी आईटीसी (ITC) को दिल्ली हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। कंपनी के मशहूर उत्पाद 'आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा' के पैकेट पर '100%' लिखने को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी थी। लेकिन अब अदालत ने फूड रेगुलेटर से कहा है कि वो अगली सुनवाई तक लाइसेंस कैंसल करने का कोई फैसला न ले।

कोर्ट का सख्त निर्देश

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने मंगलवार को आईटीसी की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने साफ कहा कि 9 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। अदालत ने FSSAI को निर्देश दिया है कि वो फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई न करे। अदालत ने फूड रेगुलेटर समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर उनका जवाब भी मांगा है।

क्या है पूरा विवाद

FSSAI ने 28 मई को एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें सभी फूड कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने लेबल, पैकेजिंग या विज्ञापनों में '100%' शब्द का इस्तेमाल न करें। इसी के तहत रेगुलेटर ने 10 अगस्त को आईटीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब 30 दिन में देना था। इसके ठीक तीन दिन बाद 13 अगस्त को एक 'इंप्रूवमेंट नोटिस' भी थमा दिया गया। इसमें 15 दिन के अंदर पैकेट से '100%' शब्द हटाने की शर्त रखी गई थी।

आईटीसी की क्या है दलील

आईटीसी के वकील रोहित शर्मा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि FSSAI की ये एडवाइजरी पूरी तरह से मनमानी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत कंपनियों को नियमों का पालन करना होता है, लेकिन रेगुलेटर अपनी मर्जी से कानून के बाहर जाकर कोई एडवाइजरी नहीं थोप सकता। आईटीसी ने ये भी तर्क दिया कि 2020 के लेबलिंग नियमों तथा 2018 के विज्ञापन नियमों में '100%' लिखने पर कोई पाबंदी नहीं है।

FSSAI ने भी दर्ज कराई अपनी आपत्ति

सुनवाई के दौरान FSSAI ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। रेगुलेटर का कहना था कि दिल्ली हाईकोर्ट के पास इस चुनौती को सुनने का अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) ही नहीं है। इस तकनीकी पेंच को सुलझाने के लिए अदालत ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर एक संक्षिप्त नोट दाखिल करें। अब सबकी नजरें 9 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

इस्लामाबाद के अस्पताल में AC ब्लास्ट से आग, 15 नवजातों की मौत

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक सरकारी अस्पताल में बुधवार सुबह आग लगने से 15 नवजात बच्चों की मौत हो गई। हादसा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) के महिला और बाल स्वास्थ्य वार्ड में हुआ। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बने नर्सरी वार्ड में 16 नवजात बच्चे भर्ती थे। PIMS वही अस्पताल है, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदालत के आदेश पर हेल्थ चेकअप के लिए लाया गया था। पाकिस्तान के जियो न्यूज के अनुसार, सुबह करीब 6:45 बजे AC का कंप्रेसर फट गया, जिसके बाद वार्ड में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बच्चों को बचाने का मौका नहीं मिल सका। रेस्क्यू टीम ने खिड़की का शीशा तोड़कर वार्ड में प्रवेश किया। रेस्क्यू अधिकारियों के मुताबिक, केवल एक नवजात बच्चे को जिंदा बचाया जा सका। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि 14 बच्चों के शव आग में पूरी तरह जल गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हादसे पर दुख जताया है और जांच के आदेश दिए है। शहबाज ने कहा है कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अब अस्पताल में आग से प्रभावित जगह को ठंडा करने का काम किया जा रहा है। हादसे की जांच के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी आग लगने की वजह और अस्पताल में सुरक्षा इंतजामों की जांच करेगी। कमेटी को 24 घंटे के अदंर रिपोर्ट सबमिट करनी है। हादसे की जानकारी मिलते ही 6 दमकल गाड़ियां और 4 एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। रेस्क्यू टीम ने लोगों को बाहर निकालने का काम किया।

होर्मुज में जहाजों के लिए अस्थायी कॉरिडोर, ईरान-ओमान में बनी सहमति

तेल अवीव, एजेंसी। ईरान और ओमान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू करने के लिए एक अस्थायी समुद्री रास्ता बनाने पर चर्चा की है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ तनाव और आर्थिक दबाव के बीच ओमान के साथ इस मुद्दे पर बातचीत दोबारा शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच पिछले कई हफ्तों से इस जलमार्ग को लेकर बातचीत चल रही थी। मंगलवार को ईरान और ओमान ने जॉइंट टेंपररी नेविगेशनल कॉरिडोर बनाने पर चर्चा की। दोनों देश इस रास्ते से सी माइंस हटाने पर भी सहमत हुए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि होर्मुज स्ट्रेट से सभी माइंस हटा दी गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी

लड़ाई अब काफी कम हो गई है, लेकिन दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए होर्मुज से गुजरना अभी भी खतरनाक बना हुआ है।

टैंकर पर हमला, खतरा बरकरार

मंगलवार को ओमान के अश शिशाह इलाके से करीब 9 नॉटिकल मील यानी 17 किमी उत्तर-पूर्व में एक तेल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। हमले के बाद टैंकर चल नहीं सका। ब्रिटेन के यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने इसकी जानकारी दी। इसी दिन अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने कहा कि उसे ईरानी सरकारी टीवी पर दिखाए गए एक वीडियो की जानकारी है। वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 20 साल के बेटे बैरन ट्रंप की हत्या की कथित साजिश की चर्चा की गई। इसमें दावा किया गया कि बैरन की निगरानी की जा रही है और उसकी हत्या के लिए 1 करोड़ डॉलर का इनाम रखा गया है।

ईरान पर अमेरिका का दबाव बढ़ा

अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाते हुए उन देशों को सजा देने की धमकी दी है, जो ईरान के साथ कारोबार जारी रखेंगे। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वह तुरंत प्रतिबंध नहीं लगाएगा। वहीं, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कुछ दूतावासों में कर्मचारियों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। ये कर्मचारी ईरान के साथ तनाव बढ़ने पर वापस बुलाए गए थे। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका को फिलहाल संघर्ष बढ़ने का खतरा कम लगता है। हालांकि कुछ दूतावास अभी पूरी क्षमता से काम नहीं करेंगे।

युद्ध से ट्रंप की लोकप्रियता भी घटी

रॉयटर्स/इप्सोस के सर्वे के मुताबिक, अमेरिका में युद्ध को लेकर जनता का समर्थन संघर्ष शुरू होने के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ट्रंप की लोकप्रियता भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। नवंबर में अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव होने हैं। इस संघर्ष में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर ईरान और लेबनान के लोग हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की पारंपरिक सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति अभी साफ नहीं है। अमेरिका और इजराइल इसे खत्म करना चाहते हैं।

विदेश मंत्रालय ने खारिज की यूएन समिति की रिपोर्ट, कहा- यह दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र की 'नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति' (UNCERD) की भारत को लेकर जारी की गई रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि हम राजनीतिक रूप से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण संदर्भों को खारिज करते हैं। साथ ही यह भी याद दिलाया कि CERD की स्थापना में भारत की अहम भूमिका रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने (UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, UNCERD) प्रेस रिलीज जारी कर रिपोर्ट में किए गए 'राजनीतिक रूप से प्रेरित और अत्यंत दुर्भावनापूर्ण' संदर्भों को पूरी तरह खारिज कर दिया। जायसवाल ने कहा कि ऐसे संदर्भों को जिस

अवमानना के वे हकदार हैं, उसी के साथ खारिज किया जाता है।

MEA ने यह भी बताया कि जिनेवा स्थित भारतीय मिशन CERD Review के बाद पहले ही विस्तृत प्रेस रिलीज जारी कर चुका है। जायसवाल ने कहा कि 11-12 अगस्त को जिनेवा में हुई ICERD की 11वीं आवधिक समीक्षा (Periodic Review) एक नियमित ट्रीटी बॉडी रिव्यू (Treaty Body Review थी) हुई थी जिसमें, भारत ने रचनात्मक भावना के साथ हिस्सा लिया था।

विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को लेकर क्या कहा

उन्होंने बताया कि भारत ने समीक्षा बैठक के दौरान संवैधानिक सुरक्षा उपायों, मजबूत कानूनी ढांचे, बहुलवाद और वंचित समुदायों की सुरक्षा की कोशिशों को सामने रखा। साथ ही कहा कि नस्लीय भेदभाव से लड़ने की हमारी प्रतिबद्धता अटूट है।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि भारत ने यह भी याद दिलाया कि 1960 के दशक में ICERD के निर्माण और मसौदा तैयार करने में भारत की अहम भूमिका रही थी। MEA के मुताबिक, भारत के अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने समीक्षा के दौरान ही व्यापक सामान्यीकरण, बिना पुष्ट प्रमाण के आरोपों और Convention के अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को खारिज कर दिया था। भारत ने यह भी कहा कि समिति की टिप्पणियों का जवाब स्थापित प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा।

रिपोर्ट में UN समिति ने क्या कहा

इससे पहले जिनेवा UN समिति ने अपने हालिया सेशन में फिनलैंड, होंडुरास, भारत और कुवैत की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में भारत के लोगों के एक बड़े हिस्से, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, दलित और रोहिंग्या शरणार्थी शामिल हैं- के मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरों को लेकर "गंभीर चिंता" जताई गई। साथ ही समिति ने यह भी कहा कि भारती ऐसे सभी आरोपों की तुरंत, गहन और निष्पक्ष जांच करे और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करे। समिति ने यह भी जिक्र किया कि इन समुदायों को "नस्लीय आधार पर हिंसा, बल का अत्यधिक प्रयोग, गैर-न्यायिक हत्याएं, उचित प्रक्रिया के बिना मनमानी और लंबी हिरासत, प्रताड़ना, दुर्व्यवहार और यौन हिंसा" का सामना करना पड़ रहा है।

अचानक मॉस्को क्यों पहुंचे सीआईए चीफ, क्या हैं इस सीक्रेट दौरे के मायने?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने मंगलवार (25 अगस्त) को मॉस्को का दौरा किया। रैटक्लिफ की मॉस्को की अचानक यात्रा से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये दौरा उस समय हुआ है जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है, जिससे हलचल पैदा हो गई है। रैटक्लिफ की यात्रा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रैटक्लिफ की इस अचानक हुई यात्रा से अमेरिका और रूस के बीच बैक चैनल बातचीत की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि CIA चीफ का रूस दौरा एक अप्रत्याशित घटना है।

रिपोर्टों के मुताबिक, CIA प्रमुख बनने के बाद रूस की जॉन रैटक्लिफ की यह पहली ज्ञात यात्रा है। बताया जा रहा है कि रैटक्लिफ ने मॉस्को में कुछ बैठकों में हिस्सा लिया, लेकिन इन बैठकों का मकसद क्या था, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अमेरिका की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी CIA के चीफ जॉन रैटक्लिफ आखिर दुनिया से छुपते-छुपाते रूस क्यों पहुंचे हैं, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

रैटक्लिफ के मॉस्को दौरे की खबर सामने आने से पहले अमेरिकी वायुसेना के एक C-17A ग्लोबमास्टर III सैन्य परिवहन विमान के रूस की राजधानी पहुंचने की खबर सामने आई थी। रैटक्लिफ इसी विमान पर सवार थे। ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Flightradar24 के डेटा के मुताबिक, अमेरिकी सैन्य विमान अमेरिका से रवाना होकर पहले लातविया गया और वहां से मॉस्को के व्नुकोवो एयरपोर्ट पहुंचा। रूसी समाचार एजेंसी TASS ने भी ऑनलाइन एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से बताया कि Boeing C-17A Globemaster III सोमवार सुबह करीब 10 बजे मॉस्को के समय के अनुसार रूस पहुंचा था। रिपोर्ट के मुताबिक, विमान अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के पास स्थित एंड्रयूज एयरफोर्स बेस से रवाना हुआ था। फ्लाइट ट्रैकिंग जानकारी के अनुसार, विमान ने पहले चार्ल्सटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट/एयरफोर्स बेस पर लैंड किया और इसके बाद लातविया की राजधानी रीगा पहुंचा। यूरोपीय संघ के हवाई यातायात नियंत्रण से जुड़े एक सूत्र ने भी TASS को बताया कि विमान रीगा से सीधे रूस की ओर गया था। Flightradar24 के डेटा में यह भी दिखाई दिया कि वही विमान मॉस्को पहुंचने के कुछ घंटे बाद वहां से रवाना हो गया। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक इस सीक्रेट यात्रा की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया है।

बच्चों के लिए विपुल साहित्य की रचना समय की जरूरत : रघुनंदन शर्मा

भोपाल। बच्चों के लिए विपुल और गुणवत्तापूर्ण साहित्य की रचना वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आज बच्चों के साहित्य की कमी महसूस की जा रही है। बच्चों के लिए अधिकाधिक साहित्य सृजन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह विचार मानस प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विचारक रघुनंदन शर्मा ने सुपरिचित लेखक संजय मेहता की पुस्तक 'एक पेड़ की कथा' के विमोचन अवसर पर व्यक्त किए।

रघुनंदन शर्मा ने कहा कि 'एक पेड़ की कथा' पर्यावरण संरक्षण के साथ किसान की कथा-व्यथा को भी प्रभावी ढंग से रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में लेखक संजय मेहता ने अपनी लेखन-यात्रा के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि 'एक पेड़ की कथा' उनकी छठवीं पुस्तक है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी बच्चों के लिए अधिकाधिक साहित्य लिखने की इच्छा है।

बच्चों के लिए लिखें बड़े लेखक: प्रो.संजय द्विवेदी

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के पूर्व महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि हिंदी में बच्चों के लिए लेखन करने वाले रचनाकारों को अपेक्षित रूप से लेखक का दर्जा नहीं दिया जाता, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्यिक लेखन की शुरुआत ही बाल साहित्य से होती है। उन्होंने वर्तमान समय में बचपन के सामने उत्पन्न हो रहे संकटों पर भी चिंता व्यक्त की।

रंगमंच के माध्यम से प्रभावी शिक्षण : चौबे

विशिष्ट अतिथि साहित्यकार एवं शिक्षाविद् डॉ. संतोष चौबे ने कहा कि वर्तमान समय में अधिकाधिक साहित्यिक कहानियों का रूपांतरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाटकों का मंचन भी व्यापक स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि रंगमंच के माध्यम से सामाजिक संदेश प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता एवं विशिष्ट अतिथि गुंजन चौकसे ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। जब इस चिंता से बच्चे जुड़ते हैं तो समाज और संसार दोनों अधिक समृद्ध होते हैं।

इस अवसर पर अनुसंधान पत्रिका 'समागम' के विशेषांक 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का विमोचन किया गया तथा लेखकों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में 'समागम गुरुकुल' का पोस्टर भी जारी किया गया। कार्यक्रम का संचालन समागम के संपादक प्रो. मनोज कुमार ने किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे सहित रंगमंच, साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े अनेक सुपरिचित हस्ताक्षर उपस्थित रहे।

स्कूल में हिजाब पहनने की नहीं मिली इजाजत, भड़के एआईएमआईएम सांसद, आदेश को बताया इस्लाम पर हमला

नई दिल्ली, एजेंसी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश की कड़ी आलोचना की है, जिसमें प्रयागराज के एक स्कूल की नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी गई थी। छात्रा ने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। मंगलवार को दारुस्सलाम स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित 'जलसा-ए-रहमतुल-लिल-आलमीन' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने हाई कोर्ट के फैसले को 'इस्लाम पर हमला' बताया। उन्होंने कहा कि जब सबरीमाला मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और संविधान के तहत किसी धर्म में किसी प्रथा की 'अनिवार्यता' पर विचार किया जा रहा है, तब हाई कोर्ट को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा,'इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया। एक लड़की स्कूल में हिजाब पहनकर जाती थी और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिजाब नहीं पहना जा सकता। मैं हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं; मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। सबरीमाला मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जहां नौ जज यह तय कर रहे हैं कि क्या जरूरी है।' आज का फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन करता है। आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि इस्लाम के लिए क्या जरूरी है? लड़कियां हिजाब अपने सिर पर पहनती हैं, दिमाग पर नहीं। यह इस्लाम पर हमला है।" मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई धार्मिक ग्रंथ या अन्य सामग्री पेश करने में नाकाम रही, जिससे यह साबित हो सके कि स्कार्फ पहनना उसके धर्म का ऐसा "जरूरी" हिस्सा है।

बिकिनी पहन पूल में उतरीं वाणी कपूर, तस्वीरें देख फैंस बोले- तबाही

बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री वाणी कपूर अपकमिंग फिल्म बदतमीज गिल को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उन्होंने अपने फैंस को अपनी पोस्ट के जरिए तोहफा दिया है। अभिनेत्री ने बिकनी में शानदार पोज दिए हैं। यूजर्स उनकी तस्वीरों की तारीफ कर रहे हैं।

वाणी कपूर अपने 38वां जन्मदिन के खास मौके पर उन्होंने ब्लू बिकनी में अपनी शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में वह स्वीमिंग पूल में पोज दे रही हैं। एक दूसरी तस्वीर में वह स्वीमिंग पूल के किनारे बैठी हैं। एक और तस्वीर में उन्होंने अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया है।

इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा... सूरज के चारों ओर एक और साल। चीजों को समझने की कम कोशिश कर रही हूं। पलों को जीने पर ज्यादा ध्यान दे रही हूं। ज्यादा जिंदगी, ज्यादा हंसी-खुशी और आगे आने वाली हर चीज के लिए तैयार हूं।

वाणी कपूर ने अपनी तस्वीरें पर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। उनकी तस्वीरों पर राशी खन्ना ने फायर वाला इमोजी कमेंट किया है। वहीं निमरत कौर ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। एक फैन ने लिखा बॉलीवुड की सबसे हॉट अभिनेत्री। एक और यूजर ने उन्हें तबाही कहा है।

आपको बता दें कि वाणी कपूर ने शुद्ध देसी रोमांस से बॉलीवुड में कदम रखा था। वह फिल्म बदतमीज गिल में नजर आने वाली हैं। इसमें उनके साथ अपारशक्ति खुराना और परेश रावल होंगे। वह जल्द ही फिल्म सर्वगुण संपन्न का हिस्सा होंगी।

महाकाली की पहली झलक ने उड़ाए होश, अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य अवतार देख पागल हुए लोग

महाकाली के मेकर्स ने फैंस का बड़ा तोहफा दिया है। मेकर्स ने महाकालीः शुक्राचार्य वॉर क्राई रिलीज किया है। इसमें शुक्राचार्य अवतार में अक्षय खन्ना और महाकाली की पहली झलक दिखाई गई है। साथ ही, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा किया है।

अक्षय खन्ना का ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी दमदार परफॉर्मेंस की एक झलक ने फैंस को पहले ही इम्प्रेस कर दिया है। धुरंधर में अपनी परफॉर्मेंस से गहरी छाप छोड़ने के बाद, एक्टर अब महाकाली के साथ अपना तेलुगु डेब्यू करने जा रहे हैं और उनके शुक्राचार्य के किरदार ने फिल्म के लिए उम्मीद और बढ़ा दी है।

फिल्म की पहली झलक में शानदार सिनेमाई पर्दे पर न सिर्फ महाकाली का रौद्र रूप नजर आ रहा है, बल्कि शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना का खौफनाक अवतार भी देखने को मिला है। अपनी पिछली फिल्म में रहमान डकैत से सबके दिलों में खौफ पैदा करने वाले अक्षय खन्ना ने महाकाली के जरिए अपने दर्शकों को यह बता दिया है कि इस फिल्म में भी उनके लिए काफी कुछ होगा। गौरतलब है कि फिल्म महाकालीÓ अगले साल 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

महाकाली की पहली झलक में धर्म और अधर्म के बीच होने वाले एक ऐसे महायुद्ध की ओर इशारा किया गया है, जो सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई तक सीमित नहीं है। असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में शुरू होने वाला यह संघर्ष एक ऐसे बड़े महायुद्ध की झलक देता है, जो पूरी दुनिया के भविष्य का फैसला करती है। दमदार सीन के साथ युद्ध की भयावह आहट और रहस्यमयी माहौल के बीच द एंड बिगिन्स का संकेत इस महायुद्ध की गंभीरता को और बढ़ाता है।

इस झलक का सबसे बड़ा आकर्षण अक्षय खन्ना हैं, जो शुक्राचार्य के किरदार में बेहद खौफनाक और दमदार नजर आ रहे हैं। उनकी तीखी नजर, प्रभावशाली व्यक्तित्व और किरदार में दिखाई देने वाली गहराई दर्शकों का ध्यान खींचती है। उनके फर्स्ट लुक से पैदा हुई उत्सुकता के बाद अब पहली झलक में उनके किरदार की वास्तविक झलक देखने को मिल रही है, जिसने फिल्म को लेकर रोमांच और बढ़ा दिया है।

इसी के साथ श्रिया रेड्डी की दमदार मौजूदगी भी कहानी में एक नया रहस्य और रोमांच जोड़ती है। फिल्म के विजुअल्स और दुनिया की बारीकी से तैयार की गई झलक इस बात का संकेत देती है कि मेकर्स दर्शकों के लिए एक बड़े स्तर का सिनेमाई अनुभव लेकर आ रहे हैं।

इस विषय में फिल्म के निर्माता रिवाज दुग्गल का कहना है, महाकाली की कहानी एक ऐसी दुनिया से आती है, जिसकी जड़ें हमारी भारतीय इतिहास में गहराई से जुड़ी हैं। हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि इसे आज के दर्शकों के लिए उस स्तर के भव्य और सिनेमाई अंदाज में पेश किया जाए, जिसके वे हकदार हैं। इस झलक के जरिए हम दर्शकों को उस दुनिया की पहली झलक दे रहे हैं, जिसकी हमने कल्पना की है। अक्षय खन्ना द्वारा शुक्राचार्य का किरदार निभाना कहानी में जबरदस्त गहराई लेकर आता है। हम दर्शकों को उस बड़े महायुद्ध का अनुभव कराने के लिए बेहद उत्साहित हैं, जिसकी शुरुआत महाकाली से होती है। हालांकि यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक बहुत बड़ी सिनेमाई यात्रा अभी बाकी है और हम दर्शकों के साथ इसे बड़े पर्दे पर साझा करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

आरके दुग्गल द्वारा प्रस्तुत और आरकेडी स्टूडियोज के बैनर तले रिवाज रमेश दुग्गल द्वारा निर्मित महाकाली का निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लूरु ने किया है। यह फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली कड़ी है। फिल्म में अक्षय खन्ना के साथ भूमि शेट्टी, श्रिया रेड्डी, रोहित सराफ और कई अन्य प्रमुख कलाकार नजर आएंगे। महाकाली 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

अजय देवगन ने दृश्यम 3 के ऑफिशियल टाइटल का किया एलान, नए पोस्टर के साथ सामने आए किरदारों के नाम

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अब अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं। सिंघम एक्टर हिंदी दृश्यम फ्रैंचाइज़ी के तीसरे पार्ट के साथ बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। अब तक इस फिल्म को दृश्यम 3 के नाम से जाना जा रहा था। लेकिन अब इसे एक टाइटल से जाना जाएगा। अजय ने दृश्यम 3 के ऑफिशियल टाइटल का एलान किया है। साथ ही फिल्म के किरदार के चेहरे से पर्दा भी हटाया गया है।

अजय देवगन ने दृश्यम 3 के कई सारे पोस्टर शेयर किए और दृश्यम फ्रैंचाइजी के आखिरी चैप्टर का एलान किया। पोस्टर के ऊपर अजय देवगन के नाम के साथ लिखा है, मेरा सच, मेरा सही, सिर्फ मेरी फैमिली है। इसी के साथ पोस्टर पर फिल्म का ऑफिशियल टाइटल दृश्यमः द कन्क्लूजन लिखा है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, हर इंसान का नजरिया अलग होता है, मेरे लिए मेरी फैमिली ही सब कुछ है।

ऐसे ही मेकर्स ने फिल्म के अन्य किरदारों के नाम के साथ पोस्ट जारी किया है। अजय के बाद तब्बू का पोस्टर रिलीज किया गया, जिससे यह साफ हुआ कि दृश्यमः द कन्क्लूजन में तब्बू का किरदार इंसाफ के लिए अपने बेटे की मौत का बदला लेने वापस आएगी।

पोस्टर पर लिखा है, इस बार मुझे जस्टिक नहीं, बदला चाहिए। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, मैंने अपना बेटा खोया है, अब हिसाब सिर्फ बदले से होगा। इसी तरह मेकर्स ने श्रिया सरन, रजत कपूर, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज जैसे किरदारों का भी पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें उनके लक्ष्य की बात बताई गई है।

दृश्यमः द कन्क्लूजन को स्टार स्टूडियो 18 और पैनोरमा स्टूडियोज ने सपोर्ट किया है। इसे अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने आमिल कियान खान और परवीज शेख के साथ मिलकर फिल्म भी लिखी है। आलोक जैन, अजीत अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं।

यह फ्रैंचाइजी गोवा के एक शांत स्वभाव वाले फैमिली मैन विजय सलगांवकर पर आधारित है, जो अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी समझदारी और जुगाड़ का इस्तेमाल करता है और उनके घर में एक मर्डर होने के बाद उन्हें कानून से बचने में मदद करता है।

तीसरे पार्ट में अजय देवगन विजय सलगांवकर का अपना रोल फिर से करेंगे, जबकि तब्बू आईजी मीरा देशमुख और श्रिया सरन नंदिनी के रोल में लौटेंगी। रजत कपूर भी अपना रोल फिर से करेंगे, जबकि प्रकाश राज और जयदीप अहलावत नए रोल में कास्ट में शामिल हुए हैं। शूटिंग पूरी हो चुकी है, और फिल्म अभी पोस्ट-प्रोडक्शन में है। यह फिल्म गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालयः S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website : aryavartkranti.com
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्कः 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com